साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 24 अगस्त से 30 अगस्त 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 02
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनेगा अग्रणी

पेज 08
वाह साहब; रोक नहीं सके तो मुंह मोड़ लिए

वर्ष : 02 अंक : 25 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 04 ग्रेन एटीएमः उंगली करो, चावल धरो, बिचौलियों को बाहर करो...!

पेट्रोल ने दौड़ाया, शक्कर ने रुलाया

ईंधन महंगा तो ढुलाई महंगी, ढुलाई महंगी तो रोजमर्रा का सामान भी जेब पर भारी

शहरसत्ता /रायपुर। छह महीनों की कहानी सिर्फ महंगे दामों की नहीं, बल्कि बदलती कीमतों और बढ़ती अनिश्चितता की है। पेट्रोल-डीजल की हालिया बढ़ोतरी ने परिवहन और कारोबार की लागत बढ़ाई, तो अब शक्कर की कीमतों में तेज उछाल ने रसोई और मिठाई कारोबार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई अभी नियंत्रण से बाहर नहीं दिखती, लेकिन आम परिवार के लिए सवाल यह है कि महीने के अंत में बचता कितना है? भारत में महंगाई की कहानी हमेशा आंकड़ों से शुरू होती है, लेकिन खत्म रसोई के बजट पर होती है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.45 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 5.52 प्रतिशत रही। जून में यही दरें क्रमशः 4.38 और 5.32 प्रतिशत थीं।

एक तथ्य को साफ रखना जरूरी है—यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में लगातार छह महीनों से खुदरा महंगाई हर महीने बढ़ रही है। फरवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई 3.21 प्रतिशत थी, मार्च में 3.40, अप्रैल में 3.48, मई में 3.93, जून में 4.38 और जुलाई में 4.45 प्रतिशत। यानी छह महीने से लगातार तेज होती महंगाई का दौर सामने आया है। लेकिन आम आदमी के लिए प्रतिशत की यह सीढ़ी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी बाजार की सीढ़ी—जहाँ पेट्रोल भरवाने पर जेब हल्की होती है, सब्जी खरीदने पर थैला हल्का होता है और अब शक्कर खरीदने पर मिठास भी महंगी लगने लगी है।

महंगाई का असर: परिवार का बदलता गणित

महंगाई का असर हर परिवार पर समान नहीं पड़ता। एक उच्च आय वाले परिवार के लिए पेट्रोल में ₹5 या शक्कर में ₹10 की बढ़ोतरी शायद महीने के बजट में आसानी से समा जाए। लेकिन कम आय वाले परिवार के लिए यही वृद्धि किसी दूसरी जरूरत में कटौती बन सकती है। यही कारण है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और परिवार की महसूस की जाने वाली महंगाई अलग-अलग दिखाई दे सकती है। सरकारी CPI एक बड़ी टोकरी के आधार पर औसत कीमतों में बदलाव मापता है। खाद्य महंगाई फरवरी के 3.47 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई में 5.52 प्रतिशत हुई। यानी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खाने-पीने की चीजें महंगी हुई हैं जिससे उनके मासिक खर्चों में बढ़ोतरी और बचत में कमी आई है।

पेट्रोल-डीजल का झटका, असर पूरे बाजार पर

महंगाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका असर अकेले उसी वस्तु तक सीमित नहीं रहता। पेट्रोल और खासकर डीजल इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। मई 2026 में वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इसका सीधा असर रायपुर में भी दिखाई दिया। बढ़ोतरी के बाद रायपुर में पेट्रोल करीब ₹103.56 और डीजल ₹96.55 प्रति लीटर पहुंच गया। इसके बाद भी कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमा नहीं। 19 मई और 22 मई को हुई बढ़ोतरी के बाद 23 मई तक रायपुर में पेट्रोल करीब ₹105.19 और डीजल ₹98.29 प्रति लीटर पहुंच गया। यह मई में ईंधन कीमतों में लगातार तीसरी बढ़ोतरी थी। मई के अंत तक रायपुर में पेट्रोल ₹108.06 और डीजल ₹101.32 प्रति लीटर तक पहुंच गया। यानी महीने की शुरुआत की तुलना में पेट्रोल में करीब ₹7.6 और डीजल में करीब ₹8 प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

यही वह जगह है जहाँ पेट्रोल-डीजल केवल पेट्रोल पंप की समस्या नहीं रह जाते। ट्रक का डीजल महंगा होता है तो माल ढुलाई महंगी होती है। माल ढुलाई महंगी होती है तो मंडी से शहर तक आने वाली सब्जियों, फलों, अनाज और दूसरे सामान की लागत बढ़ सकती है। बस, टैक्सी और दूसरे परिवहन साधनों की लागत बढ़ती है। छोटे कारोबारी के लिए डिलीवरी महंगी होती है। निर्माण क्षेत्र में मशीनरी और सामग्री की ढुलाई महंगी होती है। अर्थात पेट्रोल-डीजल की कीमत का असर दिखाई एक जगह देता है, लेकिन महसूस कई जगह होता है। रायपुर में पेट्रोल पंप पर बढ़ा हुआ भाव आखिरकार बाजार की कीमतों में भी अपना हिस्सा मांगने लगता है—और उसका बिल अंततः आम आदमी की जेब से निकलता है।

अब शक्कर की मिठास पर सबसे बड़ा झटका

अगर पेट्रोल-डीजल महंगाई का इंजन है, तो इस समय शक्कर उसकी सबसे चर्चित नई कहानी बन चुकी है। अगस्त में शक्कर की कीमतों ने असामान्य तेजी दिखाई है। उपलब्ध उपभोक्ता मामलों के आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त को भारत में खुदरा शक्कर की औसत कीमत लगभग ₹55.7 प्रति किलो पहुंच गई थी, जबकि एक साल पहले यह लगभग ₹46.3 प्रति किलो थी। यानी सालाना आधार पर करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी। सिर्फ एक महीने पहले औसत कीमत लगभग ₹48.2 थी और एक सप्ताह पहले ₹50.9—यानी तेजी ने हाल में अचानक रफ्तार पकड़ी।

यहीं से रसोई का सवाल शुरू होता है। चाय में एक चम्मच शक्कर डालने वाला परिवार शायद सोच सकता है कि ₹5-10 का फर्क क्या है। लेकिन शक्कर सिर्फ चाय की वस्तु नहीं है। इसका इस्तेमाल मिठाइयों, बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों, होटल-रेस्तरां और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में होता है। इसलिए शक्कर की कीमत में तेजी का असर केवल किराना दुकान की शेल्फ तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के प्रमुख बाजार कोल्हापुर में थोक कीमतें अगस्त में ₹4,716 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थीं। बाजार सूत्रों ने कीमतों में एक महीने में लगभग 10 प्रतिशत की तेजी बताई थी। हाल की रिपोर्टों में कुछ इलाकों में खुदरा कीमत ₹60-65 प्रति किलो तक पहुंचने की बात भी सामने आई है। गुजरात में मिठाई कारोबार से जुड़े लोगों ने लगभग ₹60 प्रति किलो के स्तर पर चिंता जताई, जबकि असम के बराक वैली क्षेत्र में करीब ₹65 प्रति किलो कीमत रिपोर्ट हुई।

शक्कर महंगी क्यों हुई?

पहला कारण है आपूर्ति की चिंता

चीनी के उत्पादन को लेकर इस साल अनुमान कमजोर हुए हैं। सरकार के अनुसार उत्पादन में करीब 11 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है और इसका प्रमुख कारण खराब मानसून तथा गन्ने की पैदावार पर असर बताया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि इथेनॉल उत्पादन के कारण उपलब्धता में कमी आने की धारणा सही नहीं है।

दूसरा कारण है मौसम

गन्ना पानी की अधिक जरूरत वाली फसल है। बारिश के पैटर्न में बदलाव और कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम का असर उत्पादन की उम्मीदों पर पड़ा है। बाजार में जब आने वाले महीनों की आपूर्ति को लेकर चिंता पैदा होती है तो व्यापारी भविष्य की कीमतों को ध्यान में रखकर स्टॉक बढ़ाने लगते हैं।

तीसरा कारण है त्योहारी मांग

भारत में अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों का लंबा मौसम रहता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दशहरा और दिवाली जैसे अवसरों पर मिठाइयों और मीठे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। ऐसे समय में अगर बाजार में स्टॉक कम होने की धारणा बन जाए तो कीमतों पर दोहरा दबाव आता है—आपूर्ति सीमित और मांग ज्यादा।

सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, लेकिन सवाल बाजार का है

शक्कर की कीमतों में तेजी को देखते हुए सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक शक्कर कारोबारियों के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट लागू की है। सरकार का उद्देश्य जमाखोरी, सट्टेबाजी और कृत्रिम कमी को रोकना तथा घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है। 19 अगस्त को सरकार ने बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए भी स्टॉक सीमा और कड़ी कर दी। सितंबर से नवंबर के बीच महीने में 10 टन से अधिक शक्कर इस्तेमाल करने वाले बड़े उपभोक्ताओं को 15 दिनों से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम ऐसे समय आया है जब कीमतों में कुछ ही दिनों में तेज उछाल देखा गया। सरकार की चिंता साफ है—अगर बाजार में वास्तविक कमी से ज्यादा कमी की अफवाह फैलती है तो कीमतें और तेजी से ऊपर जा सकती हैं। यानी महंगाई में कभी-कभी माल की कमी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कमी का डर।

क्या महंगाई आगे और बढ़ेगी?

इसका निश्चित जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी।

पहली—कच्चे तेल की कीमत।

अगर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में तनाव बना रहता है और ब्रेंट लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो भारत का आयात बिल और ईंधन लागत दबाव में रह सकती है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा आयात करता है।

दूसरी—मानसून और कृषि उत्पादन।

खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखने में मौसम की भूमिका बहुत बड़ी है। खासकर गन्ने जैसी फसलों में उत्पादन की स्थिति शक्कर की कीमतों को प्रभावित करेगी।

तीसरी—सरकारी हस्तक्षेप।

स्टॉक लिमिट, आयात-निर्यात नीति, बफर स्टॉक और बाजार निगरानी जैसे कदम कीमतों की तेजी को सीमित कर सकते हैं। शक्कर के मामले में सरकार पहले ही स्टॉक नियंत्रण जैसे कदम उठा चुकी है।

साप्ताहिक शहर सत्ता
हम निभाएंगे आपका...

30 अगस्त 2026 को NEET-PG परीक्षा 2026 आयोजित

शहर सत्ता/रायपुर। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-PG Examination 2026 का आयोजन 30 अगस्त 2026 को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक संचालित होगी।परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर रायपुर उपेन्द्र किण्डो एवं पुलिस विभाग से सहायक पुलिस आयुक्त सुश्री नंदनी ठाकुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

साय सरकार में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का कार्य निरंतर गति से जारी है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद प्रथम कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने एवं निर्माण का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया है। पुराने एवं नए वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। श्री शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। यह उपलब्धि पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण की गति को बनाए रखते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2011 एवं 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, वर्तमान में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को शीघ्रता से उनके पक्के मकान का लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का होगा सम्मान

शहर सत्ता/रायपुर। श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित श्अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजनाश् के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज परिसर के पास, जी.ई. रोड, रायपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन अतिविशिष्ट अतिथि तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, श्रमिक परिवारों तथा प्रदेशभर से आए हितग्राहियों की सहभागिता रहेगी।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनेगा देश का अग्रणी राज्य : मुख्यमंत्री

मार्च 2027 तक प्रदेश के 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य

रायपुर। सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है और छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी सौर ऊर्जा की अपनी अपार संभावनाओं का उपयोग करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूती दे रहा है। प्रदेश में मार्च 2027 तक 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'संवाद' कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों, वेंडर्स, बैंकिंग संस्थाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाने वाला यह अपनी तरह का पहला बड़ा आयोजन है। अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभव और सुझावों का यह सार्थक संवाद छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के विस्तार को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऊर्जा विकास की बुनियादी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में पहले से ही मजबूत स्थिति में है और वर्तमान में प्रदेश में लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग ₹3 लाख 50 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिनसे आने वाले समय में लगभग 30 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता विकसित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा के साथ ग्रीन एनर्जी के अधिकतम उपयोग पर विशेष जोर दे रहे हैं। सूर्य हमें प्रकृति से प्राप्त स्वच्छ, अक्षय और प्रचुर ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है।

सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इस राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पंचायत एवं विकास विभाग की योजनाओं की कलेक्टर ने की गहन समीक्षा

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में पंचायत एवं विकास विभाग की योजनाओं एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन ने वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, 15वें वित्त आयोग, समर्थ पंचायत पोर्टल, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाले ग्रामीण विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू कराने, प्रगतिरत कार्यों को गति देने और पूर्ण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में वीबी-जी राम जी के तहत स्वीकृत कार्यों की पंचायतवार समीक्षा की गई। स्वीकृत शौचालयों में कार्य प्रारंभ होने की स्थिति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने जहां कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। बालिका शौचालय, सोकपिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन, किचन शेड सहित अन्य स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वीकृत किचन गार्डन के कार्य जहां शुरू नहीं हुए हैं, वहां जल्द कार्य प्रारंभ कराया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जर्जर एवं अनुपयोगी भवनों और शौचालयों को नियमानुसार डिस्मेंटल करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

विष्णु भैया के सुशासन में विष्णुभोग की महक से महक रहा जीपीएम

रायपुर। छत्तीसगढ़ का 25वां नवगठित जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ अब विशिष्ट कृषि उत्पाद सुगंधित विष्णुभोग चावल के कारण भी नई पहचान बना रहा है। भारत सरकार की एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत विष्णुभोग चावल को जिले के प्रमुख उत्पाद के रूप में चुना गया है। मनमोहक सुगंध, उत्कृष्ट स्वाद और पारंपरिक खेती की विशेषताओं के कारण विष्णुभोग चावल आज जीपीएम जिले की विशिष्ट पहचान बन चुका है। विष्णुभोग की महक अब खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की सीमाओं को पार कर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच रही है। पेंड्रा क्षेत्र में लगभग 1,500 किसान करीब 600 एकड़ भूमि में विष्णुभोग धान की खेती कर रहे हैं। किसानों की मेहनत, सामूहिक प्रयास और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदमों ने इस विशिष्ट धान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। विष्णुभोग की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। विष्णुभोग चावल की खेती से लेकर उसके प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन तक महिलाओं की भागीदारी इसे आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी बना रही है। मलनिया महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पेंड्रा द्वारा किसानों से विष्णुभोग धान की खरीदी की जाती है। इसके बाद मिनी राइस मिल में धान का प्रसंस्करण कर आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ली फॉलोअप टीएल बैठक

बायोमेट्रिक उपस्थिति, डेंगू जांच और पीएम सूर्य घर योजना की भी हुई समीक्षा

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट में फॉलोअप टीएल बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में बकेट क्लेम, नागरिक पट्टों, पी.ओ. पोर्टल, आर.आर.सी., पीएम किसान निधि सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने स्कूलों में फिजिकल ग्राउंड, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र बनाने की स्थिति, अविवादित नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा करते हुए नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मेडिकल चेकअप की स्थिति, डेंगू जांच तथा स्वच्छता से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के देयकों के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में ई-ऑफिस, प्रोजेक्ट पुनर्जीवन, नागरिक निकायों में पेंशन प्रकरणों एवं पी.एम. श्री योजना की समीक्षा की गई। सेवा से हटने वाले कर्मचारियों के प्रकरणों को नियमानुसार समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए।

पी.एम. सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीएल बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए अगली बैठक से पूर्व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

एयरपोर्ट की 10 किलोमीटर परिधि में 41 वेस्ट डंप साइट चिन्हांकित

सफाई एवं प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार

रायपुर। विमानन एवं पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में 13 अगस्त 2026 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में रायपुर एयरपोर्ट की 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित वेस्ट डंप साइटों के चिन्हांकन, सफाई एवं समुचित प्रबंधन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत एयरपोर्ट की 10 किलोमीटर परिधि में कुल 41 स्थानों को वेस्ट डंप साइट के रूप में चिन्हांकित किया गया है।

चिन्हांकित सभी स्थलों की सूची जियो-टैग लोकेशन, अक्षांश (Latitude) एवं देशांतर (Longitude) सहित तैयार की गई है। इससे प्रत्येक वेस्ट डंप साइट की सटीक पहचान एवं स्थलवार निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन के निर्देशानुसार जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), रायपुर की जिला एवं विकासखंड स्तरीय टीम द्वारा 21 अगस्त को चिन्हांकित स्थलों का स्थल निरीक्षण एवं सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक स्थल की वर्तमान स्थिति, कचरे की मात्रा एवं सफाई की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हांकित वेस्ट डंप साइटों की समुचित सफाई, कचरे के प्रबंधन तथा भविष्य में इन स्थानों पर दोबारा कचरा डंपिंग रोकने के लिए स्थलवार कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसी क्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री बिश्वरंजन द्वारा विभिन्न चिन्हांकित स्थलों का भ्रमण कर मौके पर चल रही कार्रवाई का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं मैदानी अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए चिन्हांकित स्थलों की प्रभावी सफाई एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Chhattisgarh
full of surprises
Chhattisgarh Tourism Board

छत्तीसगढ़ पर्यटन बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े से सावधान

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और पर्यटन सुविधाओं की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायतों को देखते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील की है। बोर्ड को ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों और माध्यमों की जानकारी मिली है, जो छत्तीसगढ़ पर्यटन के नाम पर फर्जी बुकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। ऐसे माध्यमों के जरिए पर्यटकों से ऑनलाइन भुगतान कराकर ठगी किए जाने की आशंका है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पर्यटक पर्यटन स्थलों, आवासीय सुविधाओं तथा अन्य पर्यटन सेवाओं की बुकिंग के लिए केवल छत्तीसगढ़ पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट tourism.cgstate.gov.in का ही उपयोग करें। किसी अन्य वेबसाइट, अनधिकृत बुकिंग लिंक, संदिग्ध मोबाइल नंबर, विज्ञापन अथवा सोशल मीडिया के ऐसे पेज पर भरोसा नहीं करें, जो छत्तीसगढ़ पर्यटन की बुकिंग उपलब्ध कराने का दावा करते हों। बोर्ड के अनुसार, साइबर ठगी करने वाले तत्व छत्तीसगढ़ पर्यटन के नाम, प्रतीक चिन्ह, पर्यटन स्थलों की तस्वीरों और अन्य प्रचार सामग्री का दुरुपयोग कर पर्यटकों को भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे तत्व आकर्षक दरों पर कमरे, पर्यटन आवास, भ्रमण पैकेज अथवा अन्य सुविधाओं की बुकिंग का झांसा देकर पर्यटकों से ऑनलाइन भुगतान कराने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित वेबसाइट और बुकिंग प्रक्रिया की प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है।

स्कूल से लौटते समय नदी में बहे 3 बच्चे, मौत

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में रविवार दोपहर से 2 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। गायत्री नगर में जगन्नाथ मंदिर के पास नाले में फंसे एक लड़के को रस्सी के सहारे खींचकर बचाया गया। वहीं बिलासपुर जिले में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे घोंघा नदी के तेज बहाव की बह गए। तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। ग्राम समडील निवासी आशुतोष जायसवाल और विजय जायसवाल ने अपनी बेटी रिद्धी (8) और सिद्धी (8) का दाखिला गांव से 2 किलोमीटर दूर नयापारा स्थित डीपी विप्र स्कूल में कराया था। शनिवार को दोनों बहनें स्कूल गई थीं। शाम 4 बजे छुट्टी होने पर उन्हें लेने के लिए आशुतोष का बड़ा बेटा अनमोल जायसवाल (7) साइकिल से स्कूल गया था। स्कूल से लौटते समय बच्चे पुल की जगह घोंघा नदी के रास्ते से घर लौट रहे थे। नदी के बीच पहुंचने पर अनमोल तेज बहाव में साइकिल संभाल नहीं पाया। इसके बाद साइकिल पर बैठी रिद्धी और सिद्धी समेत तीनों बच्चे पानी में बह गए।

ब्लैक करेंसी स्कैम, खुद बने शिकार तो बनाया सिंडिकेट

शहर सत्ता/रायपुर। बालोद जिले के कारोबारी उमेश कुमार सिन्हा से 1.13 करोड़ की ठगी के मामले में 2 महिलाओं को अरेस्ट किया गया था। इन महिलाओं से मिले सुराग से रायपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को पुणे के रिसॉर्ट से पकड़ा है। आरोपी लोगों को रकम दोगुनी करने और काले नोटों (ब्लैक करेंसी) को केमिकल से असली बनाने का झांसा देकर ठगी करते थे। बड़े होटलों और रिसॉर्ट में बुलाकर नोट बदलकर दिखाते थे। इसके बाद भरोसा जीतने के बाद अलग-अलग बहाने से लाखों-करोड़ों रुपए ऐंठ लेते थे। आरोपी खुद को 'डी ग्रुप कंपनी (दाऊद ग्रुप)' से जुड़ा बताकर लोगों पर प्रभाव डालते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह 2005 से एक्टिव था। आरोपियों ने 21 साल में 100 से ज्यादा लोगों को ठगा है। आरोपी खुद को RBI से भी रजिसटर्ड बताते थे। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले खुद इस तरह की ठगी का शिकार हुए थे। इसका बाद गिरोह बनाकर लोगों को ठगने लगे। आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ से ज्यादा कैश, 17 मोबाइल फोन, नोट के आकार के काले पेपर, कांच की प्लेटें और अन्य सामान जब्त किया गया है। गिरोह अब तक देशभर में 100 से ज्यादा लोगों से अरबों रुपए की ठगी कर चुका है

77 घंटे बाद मिला ब्लू-वाटर में डूबे आदिल का शव

दोस्तों से लगी शर्त ने ली जान, 3 दिन से SDRF-NDRF कर रही थी तलाश

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर खदान में डूबे आदिल खान (24) का शव करीब 77 घंटे बाद पानी की सतह पर मिला। 3 दिनों तक SDRF और NDRF की टीमें गहरे पानी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रहीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शनिवार देर रात शव खुद पानी के ऊपर आ गया। घटना के बाद से परिजन लगातार मौके पर मौजूद थे और आदिल के मिलने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि प्रशासन ने इंडियन नेवी से भी मदद मांगी थी। इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड की विशेष टीम रविवार को रायपुर पहुंचने वाली थी।

पानी के पार जाने की लगी थी शर्त

जानकारी के मुताबिक, आदिल 19 अगस्त की शाम 3 दोस्तों के साथ ब्लू वाटर खदान घूमने पहुंचा था। इसी दौरान दोस्तों के बीच पानी के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने की शर्त लगी। आदिल और उसका एक दोस्त पानी में उतर गए। तैरते हुए आदिल धीरे-धीरे गहरे हिस्से की तरफ चला गया और देखते ही देखते पानी में डूब गया। घटना का वीडियो भी सामने आया था।

आदिल के डूबने की सूचना के बाद माना थाना पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। बाद में NDRF की टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। टीमों ने कई घंटे तक पानी के अंदर सर्च किया, लेकिन आदिल का पता नहीं चल पाया। ब्लू वाटर की गहराई और पानी के अंदर कम तापमान के कारण गोताखोरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब 3 दिन तक लगातार तलाश के बावजूद जब आदिल नहीं मिला तो परिजनों की चिंता बढ़ती गई। रेस्क्यू टीमें संभावित स्थानों पर लगातार सर्च करती रहीं। करीब 77 घंटे बाद शनिवार देर रात आदिल का शव पानी की सतह पर दिखाई दिया।

पहले भी हो चुके हैं हादसे

इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। यहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में 10 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करने और पूरे इलाके में फेंसिंग कराने की बात कही गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी ब्लू वाटर क्षेत्र को प्रतिबंधित करने और सुरक्षा के लिए फेंसिंग कराने की जानकारी दी है।

MBBS नीट मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट पर सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की एमबीबीएस नीट मेरिट लिस्ट में 9 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट और कैटेगरी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पूरे मामले में NSUI ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं जांच के साथ पूरी मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने की मांग कैंडिडेट्स ने की है। हालांकि, अभी किसी भी अभ्यर्थी के खिलाफ अनियमितता साबित नहीं हुई है। शिकायतकर्ताओं ने भी कहा है कि उनका उद्देश्य किसी विद्यार्थी को दोषी ठहराना नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि संबंधित डॉक्यूमेंट की जांच सक्षम अथॉरिटी से कराई जाए। कुल 9 अभ्यर्थियों के मामलों को जांच के लिए सामने रखा गया है। इनमें सबसे ज्यादा सवाल दो अलग-अलग राज्यों के डोमिसाइल से जुड़े हैं। कुछ मामलों में जाति प्रमाण-पत्र और कैटेगरी, जबकि एक मामले में पिछले साल और इस साल दर्ज कैटेगरी अलग होने का दावा किया गया है। NSUI के हेमंत पाल ने बताया पूरी मेरिट लिस्ट और सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच होने पर इसी तरह की दूसरी विसंगतियां भी सामने आ सकती हैं। इसीलिए मांग केवल इन 9 अभ्यर्थियों की जांच तक सीमित नहीं रखी गई है। पूरी एमबीबीएस नीट मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग की गई है।

कृषि विश्वविद्यालय ने प्लांट पैथोलॉजी का पेपर भी किया रद्द

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 7 अगस्त को हुई बीएससी कृषि प्रथम वर्ष की प्लांट पैथोलॉजी परीक्षा का पेपर भी रद्द कर दिया है। रायपुर पुलिस की जांच में पता चला कि 20 अगस्त के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने यह प्रश्न पत्र भी लीक किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रविवार को आपात बैठक बुलाकर पेपर निरस्त करने का फैसला लिया। इससे पहले 20 अगस्त को बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष का एंटोमोलॉजी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। अब दोनों परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएंगी।

विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक, रायपुर पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 7 अगस्त को हुई प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा का पेपर भी लीक किया था। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने यह पेपर रद्द करने का फैसला लिया।

दुर्ग के भारतीय कृषि महाविद्यालय को नोटिस

पेपर लीक मामले में भारतीय कृषि महाविद्यालय, दुर्ग को भी नोटिस जारी किया गया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित नहीं कर पाने के मामले में कॉलेज के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने का फैसला लिया है। 20 अगस्त के एंटोमोलॉजी पेपर लीक मामले में रायपुर पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए कॉलेज के दोषी पाए गए छात्रों के खिलाफ भी विश्वविद्यालय स्तर पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में विश्वविद्यालय की ओर से नियुक्त किए गए ऑब्जर्वरों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण

पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में मिलेगा फायदा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने वाला बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इसके लिए सरकार ने 'अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026' का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। इसका लाभ खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा। इन पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। इससे चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे। नियम के अनुसार, आरक्षण का फायदा उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा पूरी की है। इसके बाद वे राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में आरक्षण ले सकेंगे। हालांकि उन्हें संबंधित पद की पढ़ाई, उम्र और दूसरी जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

नाबालिग-नवजात रेप-बिक्री केस. एक और आरोपी गिरफ्तार

शहर सत्ता/रायपुर। नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने, फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रसव कराने और नवजात शिशु की बिक्री के मामले में रायपुर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय पिंटू सिंह के रूप में हुई है। वह रायपुर के दलदल सिवनी इलाके का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी के बाद मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ और जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कराने की जानकारी सामने आई। जांच में पता चला कि आरोपी महिला पूनम सागरिया ने नाबालिग की असली उम्र छिपाकर उसे बालिग दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उसने नाबालिग के नाम में बदलाव कर फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। इसके लिए पीड़िता का आधार कार्ड दलदल सिवनी निवासी पिंटू सिंह को दिया गया था।

इस वर्ष भी तीजा में अयोध्या से आएगी माता कौशल्या

ग्राम चंदखुरी में माता कौशल्या संग तीजा तिहार का आयोजन

रायपुर। चित्रोत्पला लोक कला परिषद द्वारा 2023 से लगातार 'माता कौशल्या संग तीजा तिहार का आयोजन ग्राम चंदखुरी में किया जा रहा है। इस साल चौथा वर्ष है। इस कार्यक्रम के परिकल्पना तथा आरंभ करने में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित सकेश तिवारी का प्रमुख योगदान है। कार्यक्रम के संबंध में राकेश तिवारी का कहना है कलाकार साहित्यकार का दिमाग क्रियाशील रहता है ऐसे ही एक दिन 2023 में मैं कल्पना किया कि छत्तीसगढ़ का महिलाओं का प्रमुख त्योहार तीजा है। उस दिन समस्त छत्तीगढ की महिलाएं अपने मायके आती है। हमने भी पुरखों से यही सुना है कि राजा भानुवंत कौशल प्रदेश के राजा थे एवं उनकी बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ से हुआ था। इस तरह कौशल्या हमारी बहन, बुवा, माता हुई।

तो क्यों ना सब लोगों की तरह माता कौशल्या को तीजा में लेवा कर लाया जाय और यही से इस परंपरा की शुरुवात हुई। इस कार्यक्रम में अयोध्या जाकर मिट्टी लाई जाती है मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है तथा मूर्ति को पंडवानी गायिका प्रभा यादव के घर स्थापित किया जाता है और पांच दिन तक विधि विधान के साथ, जैसे एक बहन के साथ तीजा मनाते हैं उसी तरह तीजा तिहार मनाई जाती है।

दिनांक 23 अगस्त 2026 को श्रीमती प्रभा यादव, पंडवानी गायिका द्वारा अंगाकर रोटी, मुड और आचार देकर लेवालों को अयोध्या रवाना करना 25 अगस्त को लेवाल डॉक्टर परुषोत्तम चंद्राकर एवं पडित राजेश शर्मा द्वारा अयोध्या से राजा दशरथ की अनुमति पश्चात् पवित्र मिट्टी ग्रहण करना। दिनांक 26 अगस्त 2026 को रायपुर रेलवे स्टेशन में लेवालो का स्वागत। 27 अगस्त 2026 को लाई गई मिट्टी को निमोरा स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकार पीलू साहू को सौंपना। 10 सितंबर 2026 को माता कौशल्या के भव्य मूर्ति (गोवो में बालपन में राम जी, बैठे हुए) को बाजा गाजा के साथ चंदखुरी ले जाना। 11 सितंबर 2026 को माता कौशल्या की मूर्ति की स्थापना एवं पूजा पाठ सुबह और शाम छत्तीसगढ़ी भाषा में आरती एवं ठेठरी खुरमी के विशेष भंग लगाना। 12 सितंबर 2026 को बच्चों द्वारा भांचा राम के समक्ष नांदिया बैला दौड़ तथा जांता पीसने का प्रदर्शन 13 सितंबर 2026 को माता कौशल्या को करू भात खिलाकर उपवास रखना। 14 सितंबर 2026 को माता कौशल्या के सामने भजन, कीर्तन, पंडवानी, भरथरी का आयोजन रात्रि जागरण का कार्यक्रम एवं 15 सितंबर 2026 को माता कौशल्या को बासी खिलाना तथा साड़ी भेंट कर विदाई देना। यह अपने तरीके का अंगूता कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी संस्कृति को धर्म से जोड़कर सहेजने का एक प्रयास है।

जश्ने ईद मिलादुन्नबी पर 26 अगस्त को निकलेगा भव्य जुलूस

शहर सीरत कमेटी रायपुर छत्तीसगढ़ का ऐलान

रायपुर। हर साल की तरह इस साल भी जश्ने ईद मिलादुन्नबी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मुबारक मौके पर बड़े ही शान-ओ-शौकत के साथ 26 अगस्त, बुधवार को जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाएगा। जुलूस सुबह 7 बजे महबूबिया चौक, बैजनाथपारा, रायपुर से प्रारंभ होगा, जो शहर का गश्त करते हुए लगभग सुबह 10 बजे सीरत मैदान, बैजनाथपारा पहुंचेगा। यहां धर्मगुरुओं के हाथों परचम कुशाई की जाएगी। इसके पश्चात शहर सीरत कमेटी की ओर से लंगर का एहतमाम किया जाएगा।

ज्ञात हो कि यह जुलूस शहर के विभिन्न मोहल्लों से लोगों के बैजनाथपारा में एकत्रित होने के बाद मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक, शारदा चौक, फूल चौक, तात्यापारा, सत्ती बाजार, सदर बाजार एवं कोतवाली चौक होते हुए सीरत मैदान पहुंचेगा, जहां जुलूस का समापन होगा।

शहर सीरत कमेटी की ओर से तमाम लोगों से अपील की गई है कि 26 अगस्त को जुलूस-ए-मोहम्मदी में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे कामयाब बनाएं तथा अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम आम करें।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

दंत, नख के साथ पूंछ भी...

जैसे सिंह बिना दांत और तीखे नाखूनों के साथ एक लंबी पूंछ भी रखता है; जो उसे शिकार के समय संतुलन और अपने झुंड संग प्यार जताने का बेहतर माध्यम साबित होती है। ठीक इसी तरह एक बलवान शक्तिशाली पशु भी बिना पूंछ और सींग का पशु नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं; रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान, ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान। राम जी के भजन बिना जो मोक्ष-पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। मोक्ष का अर्थ यहां यह न ले लिया जाए कि मरने के बाद की कोई स्थिति। जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है। दुर्गुणों से मुक्ति हो जाए, जीवन में शांति उतर आए, परमात्मा की अनुभूति बनी रहे तो यही मोक्ष है। लेकिन इसके लिए तुलसीदास जी की शर्त है कि भगवान का भजन करते रहना चाहिए।

यहां उन्होंने पशु को पूंछ और सींग से जोड़ा है। सींग में आक्रमण है, पूंछ में सुरक्षा है। उनका कहना है कि यदि ये दोनों नहीं हैं तो वह पशु भी किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है मनुष्य में भी ये दो खूबी होनी चाहिए। खासकर आजकल की पीढ़ी में, प्रतिस्पर्धा के युग में आक्रामक होना भी आवश्यक है, लेकिन विनम्रता बनी रहे। सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। युवा पीढ़ी को इस पंक्ति को समझना होगा। कथित कलियुग में स्नेह करने वाली मां और तठस्थ दुलार करने वाला पिता दोनों बदले नहीं हैं। लेकिन बच्चे अब नुकीले दांत, तीक्ष्ण नाख़ून, पैनी सींगों वाले हो गए हैं। जेन-जी की दुनिया में जन्मदाताओं की तुलना में प्यार, दुलार अपने गेजेट्स से ज्यादा किया जा रहा है। एक आई-फोन या फिर एप्पल का टैब बच्चों के लिए रिश्तों से ज्यादा दुलारा हो गया है।

एक वक्त था जब हम भी बच्चे थे और समय पर खेलने, पढ़ने और घर के जरुरी कार्यों में माता-पिता का बटाते थे। अभावग्रस्त समय था...सरकारी नल बोरिंग से पानी टेरना या कुंओं से घर की पानी की जरुरत पूरी करना ड्यूटी थी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त हम गुस्सैल नहीं थे या विरोध-विद्रोह नहीं करते थे। जरूर करते थे और दांत, नाख़ून, सींगों के साथ हम पूंछ भी रखते थे। काश आज की जेन-जी या गेजेट्स के लिए परिवार का काल बनने वाली पीढ़ी भी दुर्गुणों से मुक्त हो जाए, उनके जीवन में शांति उतर आए, परमात्मा की अनुभूति बनी रहे। लेकिन इसके लिए तुलसीदास जी की शर्त है कि भगवान का भजन करते रहना होगा मार्ग मिल जायेगा।

यदि दिन में सपने देखना हैं तो पहले भाग्य और कर्म को समझें

इस बात की खूब चर्चा होती है कि हम अपने भविष्य के लिए सपने देखें। लेकिन अगर सपने देखना है तो पहले गहराई से सपनों को समझें। किस बात का सपना देख रहे हैं यह तो बाद की बात होगी। एक होती है डे-ड्रीमिंग, दिन में सपना देखना और दूसरा सपना रात को देखा जाता है। दिन का सपना एक योजना है, रात का सपना अनियोजित होता है।

यदि दिन में सपने देखना हैं तो दो बातों को समझें- भाग्य और कर्म। फिर अपने सपने को हो रहे परिवर्तनों से जोड़ें। दुनिया तेजी से बदल रही है तो आपकी गति कहीं रिवर्स तो नहीं है? सपने पूरे करने हों तो दूसरों का सहयोग भरपूर लें, फायदा भी उठाएं। कौन-से काम हम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसकी सूची बनाएं। और काम करते समय हमारी क्या कमजोरियां हैं, इस पर भी काम करें। क्योंकि आज अपना मकसद पूरा करने के लिए 'हसलिंग' का दौर है, यानी कड़ी मेहनत करना। अगर बातचीत की भाषा में कहें तो बिना उठापटक के, जुगाड़ के, आसानी से तो कुछ नहीं मिलता। यदि दिन में सपने देखना हैं तो पहले भाग्य और कर्म को समझें

ग्रेन एटीएमः उंगली करो, चावल धरो, बिचौलियों को बाहर करो...!

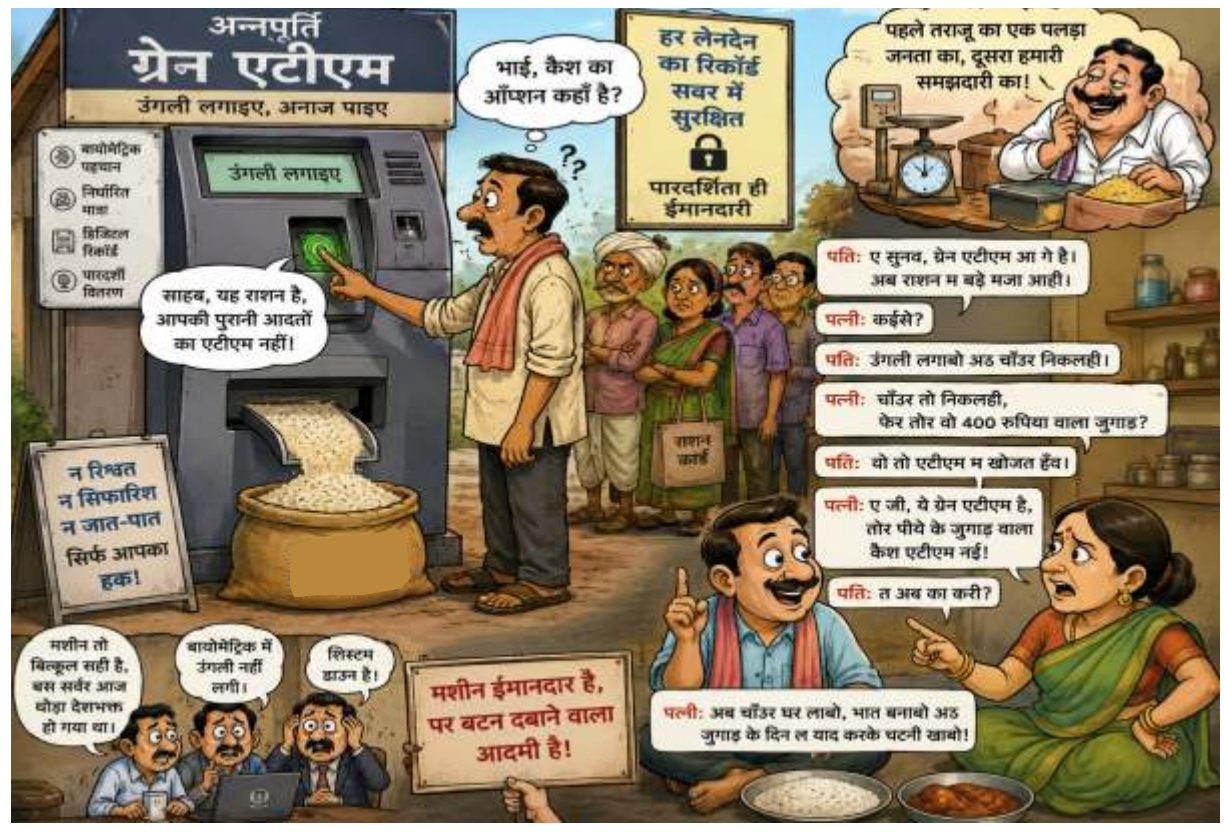

कॉलम - खुरचन
द्वारा- हरिदास

हमारे यहाँ मशीनों का बड़ा सम्मान है। आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मशीन पर किया जा सकता है। यह बात अब धीरे-धीरे सरकारी फाइलों से निकलकर राशन की दुकान तक पहुँच गई है। छत्तीसगढ़ में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की शुरुआत रायपुर, दुर्ग औरर बिलासपुर से हो चुकी है। अब राशन लेने के लिए आदमी को दुकानदार के चेहरे की ओर देखने की जरूरत नहीं; मशीन देखेगी, उंगली पहचानेगी और उतना ही अनाज देगी, जितना सरकार ने निर्धारित किया है।

पहले राशन की दुकान पर तराजू होता था। तराजू बेचारा बहुत बदनाम था। उसकी एक पलड़ा जनता का होता था और दूसरा दुकानदार की समझदारी का। जनता कहती—"भाई, पाँच किलो दिया है या साढ़े चार?" दुकानदार मुस्कुराकर कहता—"तुम्हें मशीन से तौलकर दूँ क्या?"

अब सचमुच मशीन आ गई है। मशीन को न ग्राहक की जाति पता है, न यह कि चुनाव में उसने किसे वोट दिया, न दुकानदार से उसकी पुरानी दोस्ती है। उसे केवल बायोमेट्रिक पता है और निर्धारित मात्रा। उंगली लगाइए, अनाज पाइए। मशीन न तो आँख दबाती है, न कहती है—"आज चावल कम आया है।" उसके पास बहाने का कोई विभाग नहीं है।

सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मशीन रिश्वत नहीं लेती। मशीन को देखकर आदमी असहाय हो जाता है। उसे न चाय चाहिए, न मिठाई, न "कुछ व्यवस्था"। वह डिजिटल है और डिजिटल आदमी से अधिक निर्दयी होता है। हर लेनदेन का रिकॉर्ड सर्वर पर चला जाएगा। अब अनाज का हिसाब वही रहेगा जो मशीन बताएगी। यह कालाबाजारी के लिए बहुत बुरी खबर है। कालाबाजारी हमेशा अंधेरे में फलती है और डिजिटल रिकॉर्ड उस अंधेरे में बल्ब की तरह है। लेकिन मुझे मशीन से ज्यादा डर उन लोगों से है जो मशीन चलाएँगे।

पहले चावल नहीं लेने पर 350-400 रुपए मिल जाते थे। अब ग्रेन एटीएम से चावल निकलेगा। कुछ लोग मशीन के सामने खड़े होकर पूछेंगे—"भाई, कैश का ऑप्शन कहाँ है?" मशीन कहेगी, "साहब, यह राशन है, आपकी पुरानी आदतों का एटीएम नहीं!"

हमारे यहाँ मशीन ईमानदार हो सकती है, पर मशीन का बटन दबाने वाला आदमी है। कल को कोई कह सकता है, "मशीन तो बिल्कुल सही है, बस सर्वर आज थोड़ा देशभक्त हो गया था।" कोई दूसरा कहेगा, "बायोमेट्रिक में उंगली नहीं लगी।" और तीसरा कहेगा, "सिस्टम डाउन है।"

हमने वर्षों में एक अद्भुत कला विकसित की है, व्यवस्था खराब हो तो उसे तकनीकी समस्या घोषित कर दो और तकनीकी समस्या हो तो उसे मानवीय भूल बता दो।

फिर भी ग्रेन एटीएम का स्वागत होना चाहिए। कम-से-कम इसने राशन की दुकान को उस पुराने युग से बाहर निकालने की कोशिश की है, जहाँ 35 किलो अनाज का हिसाब 35 तरह से लगाया जाता था। मशीन यह भी सिखाती है कि पारदर्शिता का अर्थ शीशे की दुकान नहीं, बल्कि ऐसा हिसाब है जिसे कोई भी जाँच सके। अगर अनाज कितना आया, कितना निकला और किसे मिला, सब डिजिटल दर्ज हो रहा है, तो चोरी करने वाले को पहली बार यह चिंता होगी कि कहीं उसका माल उससे ज्यादा ईमानदार रिकॉर्ड में न निकले।

अब असली परीक्षा मशीन की नहीं, हमारी है।

अगर मशीन सटीक तौलती रही और व्यवस्था उसकी निगरानी करती रही, तो गरीब को उसका पूरा राशन मिलेगा। लेकिन अगर हमने मशीन में भी आदमी की पुरानी आदतें भर दीं, तो एक दिन कोई कहेगा, "साहब, मशीन भी हमारी संस्कृति सीख गई है।"

तब मशीन अनाज तो तौलेगी, मगर ईमानदारी नहीं। और ईमानदारी का वजन अभी तक किसी ग्रेन एटीएम ने नापा नहीं है।

और अंत में... ग्रेन एटीएम की खबर पर गृहस्थी में कुछ अलग ही तरह की चर्चाओं का दौर जारी है—

पति: ए सुनव, ग्रेन एटीएम आ गे हे। अब राशन म बड़े मजा आही।

पत्नी: कइसे?

पति: उंगली लगाबो अउ चाँउर निकलही।

पत्नी: चाँउर तो निकलही, फेर तोर वो 400 रुपिया वाला जुगाड़?

पति: वो तो एटीएम म खोजत हँव।

पत्नी: ए जी, ये ग्रेन एटीएम हे, तोर पीये के जुगाड़ वाला कैश एटीएम नइ!

पति: त अब का करी?

पत्नी: अब चाँउर घर लाबो, भात बनाबो अउ जुगाड़ के दिन ल याद करके चटनी खाबो!

एमएसएमई को मजबूत करने के लिए अगला चरण

शोभा करंदलाजे

संसद के दोनों सदन में हाल ही में पारित किया गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संसोधन विधेयक, 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। एमएसएमई राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एमएसएमई क्षेत्र ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर 9 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं, जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई हमारी आर्थिकी में 31% तथा निर्यात में 50% योगदान देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी है। एमएसएमई भारत के विकास के सूत्रधार हैं। हाल के वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो 'उद्यम' पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या से ही स्पष्ट दिखती है, जो 1 अप्रैल 2023 को 1 करोड़ 65 लाख से बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

वर्ष 2020 में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण को, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त करके, अधिक व्यापक और समावेशी बनाया गया था। इसके तहत टर्नओवर और निवेश दोनों पर आधारित एक समग्र मानदंड विकसित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निवेश सीमा ढ़ाई गुना बढ़ाकर क्रमश: ढ़ाई करोड़, पच्चीस करोड़ और एक सौ पच्चीस करोड़ की गई है एवं टर्नओवर को दो गुना बढ़ाकर क्रमश: दस करोड़, सौ करोड़ और पांच सौ करोड़ किया गया, जिसने इन उद्यमों को पूंजी निवेश बढ़ाने, विकास और तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

वित्त की उपलब्धता एमएसएमई क्षेत्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है और इसके उल्लेखनीय परिणाम दिख रहे हैं। एमएसएमई को प्रदान किया गया बकाया ऋण, वर्ष 2014-15 में 10 लाख करोड़ रुपये था, जो कि अब बढ़कर 38 लाख 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज' (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराता है। इसके ज़रिए वर्ष 2000 से 2022 के बीच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी गई क्रेडिट गारंटी 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये थी, जो पिछले चार वर्षों में अर्थात् 2022-23 से 2025-26 तक बढ़कर 10 लाख 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक लगभग 8 लाख 34 हजार सूक्ष्म उद्यमों को 24 हजार 903 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है, जिससे अनुमानित 75 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सालाना 25% खरीद करना अनिवार्य है; इसमें महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 3% और एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4% खरीद शामिल है। विगत वर्षों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद में लगातार वृद्धि हुई है। वित्तीय-वर्ष 2020-21 में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सार्वजनिक खरीद का मूल्य 40,717 करोड़ रुपये था जो कि वित्तीय-वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,15,801 करोड़ रुपये हो गया है, जो सीपीएसई द्वारा खरीद के लिए लक्षित 25 प्रतिशत की तुलना में 49 प्रतिशत से अधिक है। इसमें एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 3,984 करोड़ रुपये की खरीद हुई और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली उद्यमों से 9,059 करोड़ रुपये की खरीद हुई है।

एमएसएमई को उनका भुगतान समय पर दिलाने हेतु मंत्रालय ने कई सार्थक प्रयास किए हैं, ट्रेड्स इनमें से एक है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे भारत में एमएसएमई की लिक्विडिटी (नकदी) संबंधी चुनौतियों तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में शुरु किया गया था। ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म ने एमएसएमई क्षेत्र को मार्च 2026 तक 8,71,000 करोड़ रुपये की इनवॉइस डिसकाउंटिंग के माध्यम से समय पर भुगतान दिलवाया है। ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े एमएसएमई की संख्या अप्रैल 2022 में 34,430 थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 2,55,000 से अधिक हो गई है। वहीं, एमएसएमई की इनवॉइस डिसकाउंटिंग की राशि वर्ष 2021-22 में 40,000 करोड़ रुपये से बढ़कर, वित्त वर्ष 2025-26 में 3,47,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। ट्रेड्स पर इनवॉइस डिसकाउंटिंग का बढ़ता चलन, भारत सरकार के एमएसएमई के समयबद्ध भुगतान के प्रति संकल्प को दर्शाता है।

इसी दिशा में विलंबित भुगतान और उससे जुड़े विवादों के निपटारे हेतु पूरे देश में 161 सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) स्थापित किए गए हैं। संशोधन में राज्यों को एमएसईएफसी की संरचना तय करने के लिए सक्षम बनाने के लिये प्रावधान लाए गए हैं जिससे आवश्यकतानुसार एमएसईएफसी का गठन किया जा सके। संबंधित पक्षों में समझौते के साथ विवाद सामाधान के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। यह संशोधन विधेयक ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को सक्षम एवं सशक्त बनाता है, ताकि संबंधित पक्षों द्वारा अपने विवादों का समयबद्ध और किफायती तरीके से हल सुनिश्चित किया जा सके।

एमएसएमई मंत्रालय महिला उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मंत्रालय की अनेक योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। आज उद्यम पोर्टल पर 39% से अधिक एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व में हैं, यानि 3.38 करोड़ के लगभग एमएसएमई महिला स्वामित्व में हैं और जिनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, महिलाओं के लिए 90% तक गारंटी कवरेज है और सालाना गारंटी फीस में 10% तक की छूट प्रदान की जाती है। खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत ट्रेड फेयर में महिला उद्यमियों की भागीदारी पर 100% सब्सिडी दी जाती है, जबकि दूसरे उद्यमियों के लिए यह 80% है। पीएमईजीपी में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 25 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति का विकास, मंत्रालय की प्राथमिकता है। आज उद्यम पर 1.24 करोड़ से अधिक एमएसएमई, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमी के स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना, एमएसएमई मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाना और उनके बीच "उद्यमिता संस्कृति" को बढ़ावा देना है।

मक्का एग्रीमेंट की खटास मिटाने तेहरान जाएंगे मुनीर!

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सोमवार (24 अगस्त) को ईरान का दौरा करेंगे. तेहरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि यह दौरा इलाके में शांति और सुरक्षा लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए है. हालांकि, मुनीर का दौरा ऐसे वक्त हो रहा, जब मक्का एग्रीमेंट में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने साइन किए हैं. वहीं, होर्मुज को लेकर अमेरिका से ईरान का विवाद बना हुआ है. पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. इसका मकसद उस युद्ध को खत्म करना है, जो फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद शुरू हुआ था. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से मुनीर के दौरे की पुष्टी की है. पहले सूत्र ने जानकारी देते हुए कहा है कि ईरान और पाकिस्तान सीधे संपर्क में हैं. दूसरे सूत्र ने कहा है कि बातचीत में संघर्ष से जुड़ी हालिया घटनाओं पर भी चर्चा होगी. इसमें ईरान पर और कड़े बैन लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी शामिल है.

अमेरिकी सेना में फूट? आर्मी सेक्रेटरी छोड़ सकते हैं पद, रिपोर्ट में दावा

वाशिंगटन। अमेरिकी सेना में एक और बड़े नेतृत्व बदलाव की खबर सामने आई है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल इस साल के अंत तक अपने पद से हट सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रिस्कॉल और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के बीच लंबे समय से तनाव की खबरें रही हैं. पीट हेगसेथ ने अप्रैल में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था. इसके बाद अभी तक उनके स्थान पर स्थायी चीफ की नियुक्ति नहीं हुई है. फिलहाल जनरल क्रिस्टोफर लानेव कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह पहले सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर थे और हेगसेथ के वरिष्ठ सैन्य सहयोगी भी रह चुके हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रिस्कॉल और उनका परिवार इस गर्मी में जॉइंट बेस मायर-हेंडरसन हॉल स्थित सरकारी आवास से बाहर चले गए. उनका परिवार नॉर्थ कैरोलिना चला गया, जबकि ड्रिस्कॉल खुद एक सैन्य ठिकाने पर छोटे अपार्टमेंट में रहने लगे.

जापान में 5.9 की तीव्रता का भूकंप

टोक्यो। जापान के पूर्वी हिस्से में रविवार तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप से टोक्यो समेत आसपास के इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए. अधिकारियों के मुताबिक, भूकंप में 23 लोग घायल हुए हैं, हालांकि ज्यादातर की चोटें मामूली हैं. भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया. झटकों के कारण कुछ ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुईं, कई घरों की बिजली गुल हुई . सरकार ने संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए टास्क फोर्स गठित की है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, भूकंप दक्षिणी इबाराकी प्रांत में आया और इसका केंद्र जमीन से करीब 70 किलोमीटर नीचे था. यह इलाका जापान के उन क्षेत्रों में शामिल है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं।

संसद में आने वाला है महिला आरक्षण-परिसीमन बिल?

नई दिल्ली। सरकार एक बार फिर से महिला आरक्षण और परिसीमन बिल सदन में लाने वाली है? इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी राष्ट्रपति ने अभी तक सत्र समाप्ति की औपचारिक मंजूरी नहीं दी है. इधर, बीजेपी की तरफ से रविवार (23 अगस्त) को एक बार फिर से अपील की गई है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास किया जाए. यह बयान बीजेपी ने राहुल गांधी की तरफ से शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किए गए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और भारत की पितृ सत्ता वाली सोच पर सवाल उठाने के बाद दिया है.

बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं से अपील की थी कि अगर महिलाओं की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार जो 2029 में उनको 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कर रही है, उस बिल को संसद से पास करवाने में मदद करें. ऐसे में सरकार ने इस बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. सरकार अब जल्द से जल्द इन दोनों बिलों को संसद से पास करवाने की कोशिश में जुटी हुई है. 13 को अगस्त को भले ही सदन का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस सत्र को औपचारिक रूप से खत्म करने की राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है.

ऐसे में चर्चाएं हैं कि सरकार इस बीच सत्र को आगे बढ़ा सकती है और सदन के पटल पर महिला आरक्षण और परिसीमन बिल टेबल पर फिर से रख सकती है. किसी भी सत्र को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होना जरूरी है. इधर, सरकार लगातार बैक डोर से इस बिल को पास कराने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है. अगले दो से तीन हफ्ते बाद सरकार सदन में बिल ला सकती है. कई विपक्षी पार्टियों ने भी इसको लेकर अंदेशा जाहिर किया है.

सत्रावसान न होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद भी अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के बाद विपक्षी नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्र अवसान (Prorogation) के बीच का समय आमतौर पर दो से चार दिन का होता है. ऐसे कई उदाहरण हैं, जब स्थगन और सत्रावसान एक ही दिन हुए हैं. इस लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए दस दिन बीत चुके हैं. लेकिन अभी भी इसके सत्रावसान के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है. यह सच है कि 2015 में मॉनसून सत्र के लिए अंतर 28 दिन का था. 2021 में यह 20 दिन का था. लेकिन तब कोई खतरानक चालें नहीं चली जा रही थीं. अब इतनी असामान्य देरी का क्या कारण है? क्या केंद्रीय गृहमंत्री अभी भी विशेष सत्र में परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए अपने उस विवादास्पद 2/3 बहुमत की तलाश में है?

हॉर्मुज अब US का', ट्रंप ने मैप शेयर कर किया दावा, ईरान का करारा जवाब

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को नया अमेरिकी इलाका बताया गया है. वहीं, ईरान का कहना है कि यह समुद्री रास्ता बंद है और तब तक बंद रहेगा जब तक वॉशिंगटन अपना रवैया नहीं बदलता. डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले 18 अगस्त को यही तस्वीर शेयर की थी. 14 अगस्त को लॉन्ग आइलैंड की एक पुलिस अकादमी में बोलते हुए उन्होंने कहा, "बहुत जल्द मैं होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का इलाका घोषित कर दूंगा."इसी बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा कि तेहरान तब तक इस जलडमरूमध्य को नहीं खोलेगा, जब तक अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं करता और अपना व्यवहार नहीं बदलता. ईरान इंटरनेशनल ने रेजाई के हवाले से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है और दोबारा नहीं खुलेगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपना व्यवहार बदलता है और अपने वादे पूरे करता है तो स्थिति अलग होगी, लेकिन इस बार अमेरिका को कदम उठाना होगा. इसे सिर्फ बातों और बातचीत से हल नहीं किया जा सकता. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स के डेटा से पता चलता है कि ईरान के ऐलान के बावजूद हाल के दिनों में इस जलमार्ग से होने वाले ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई है।

कर्नाटक में सियासी घमासान! आज विधानसभा घेरेगी BJP-JDS

बेंगलुरू। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर वाल्मीकि कॉर्पोरेशन विवाद को लेकर घमासान तेज हो गया है. विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने रविवार (23 अगस्त 2026) को ऐलान किया कि बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस 24 अगस्त को बेंगलुरु में विधान सौधा का घेराव करेगी.

विपक्ष की मुख्य मांग प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स मंत्री बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की है. आर. अशोक ने आरोप लगाया कि नागेंद्र का नाम कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित घोटाले में सामने आया है. उनके मुताबिक, इस मामले में करीब 89 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता हुई थी और इसी वजह से मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए.

आर. अशोक ने बताया कि बीजेपी सोमवार सुबह 9:30 बजे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से मार्च निकालेगी. इसके बाद कार्यकर्ता विधान सौधा का घेराव करेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र के भी प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही गई है।

भाजपा के Gen-Z प्रोग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कसा तंज

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भाजपा के नए Gen Z आउटरीच प्रोग्राम और इसके लिए चुने गए नेताओं पर तंज कसा है. सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, 'भारतीय जनता पार्टी को Gen Z के शानदार चेहरों के चुनाव के लिए तीन तालियां.' उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पुराने बयानों को लेकर उन पर भी सवाल उठाए. दास ने रविवार (23 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा कि नितिन नबीन ने पहले देश के युवाओं को वायरस और कॉकरोच करार दिया था और उसके बाद प्रदर्शन करने वाले युवाओं की तुलना टुकड़े-टुकड़े गैंग से की थी.

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'Gen Z के बीच अपने पहुंच बनाने के लिए भाजपा ने एक शानदार फैसला लिया है. नितिन नबीन ने हाल ही में युवा पीढ़ी को वायरस और कॉकरोच कहा था और प्रदर्शनकारियों को टुकड़े-टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया था.'कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से शनिवार (22 अगस्त) को अपने आगामी Gen Z आउटरीच प्रोग्राम के लिए एक डेडिकेटेड टीम का गठन करने के बाद सामने आई है।

मणिपुर में जनगणना से पहले लागू होगा NRC?

इंफाल। मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC) ने कुछ मैतेई और नागा संगठनों की उस मांग का विरोध किया है, जिसमें जनगणना से पहले राज्य में NRC लागू करने की बात कही जा रही है. KZC ने इस मांग को जल्दबाजी में उठाया गया और गलत कदम बताया है. काउंसिल के मुताबिक, NRC एक राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया है और इसे लागू करने या इसकी समयसीमा तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. किसी राज्य सरकार या किसी समुदाय को अपनी तरफ से किसी राज्य में अलग NRC शुरू करने का अधिकार नहीं है.KZC के सूचना एवं प्रचार सचिव गिन्जा वुअलजोंग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मणिपुर में आबादी और जनसांख्यिकी को लेकर कई तरह के दावे और आरोप सामने आते रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश का आतंकी अड्डा फिर एक्टिव, पाक सरकार ने दिए थे 8 करोड़

इस्लामाबाद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ठिकाने मरकज सुभानअल्लाह का व्यापक पुनरुद्धार कार्य पूरा हो गया है।हमले के एक साल से अधिक समय बाद सामने आए नए फुटेज से स्पष्ट होता है कि यह परिसर फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसके गुंबदों को दोबारा बनाया गया है, नया प्लास्टर व पेंट करने के साथ ही प्रीमियम मार्बल फ्लोरिंग लगाई गई है, जिससे धमाके के पुराने निशान पूरी तरह से ढक गए हैं। मुख्य हॉल के भीतर बने गहरे गड्ढों को कंक्रीट से भर दिया गया है, जबकि अल-साबिर मदरसे और शीर्ष कमान के आवास जैसी तबाह हो चुकी इमारतों को ध्वस्त कर वहां नया निर्माण किया गया है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने जैश-ए-मोहम्मद को 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की नकद सहायता उपलब्ध कराई, जिसमें से लगभग 11 करोड़ रुपये 15 महीने के भीतर इस मुख्य परिसर के पुनर्निर्माण पर खर्च किए गए।

बहावलपुर केंद्र की कमान में बदलाव

जैश सरगना मसूद अजहर की स्वास्थ्य समस्याओं के चलते बहावलपुर परिसर का दैनिक कामकाज अब उसके भाइयों तलहा अल-सैफ और मोहिउद्दीन औरंगजेब उर्फ अम्मार अल्वी के हाथों में चला गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मसूद अजहर और रऊफ असगर जैसे वरिष्ठ आतंकी सिंध के नवाबशाह जिले में सरकारी संरक्षण के तहत सुरक्षित ठिकानों में मौजूद हैं।

नीति आयोग की चौंकाने वाली रिपोर्ट

8.7 करोड़ युवा न पढ़ाई में, न नौकरी में!

नई दिल्ली। देश में युवाओं की पढ़ाई, रोजगार और स्किलिंग को लेकर नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट ने चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ भारतीय युवा ऐसे हैं, जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न काम कर रहे हैं और न ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं. नीति आयोग ने इसे रोजगार और कौशल विकास के मोर्चे पर बड़ी चुनौती बताते हुए युवाओं के लिए सस्ती या सब्सिडी वाली ट्रेनिंग, स्वरोजगार के अवसर और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्किलिंग कार्यक्रम बढ़ाने की जरूरत बताई है.

2021 के सर्वे के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट

नीति आयोग ने 'Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047' नाम से यह रिपोर्ट जारी की है. इसमें 8.7 करोड़ युवाओं का अनुमान 2021 में हुए नेशनल सैंपल सर्वे के 78वें दौर के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है. भारत के वर्कफोर्स और लर्नर्स को पांच प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है. इनमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, शिक्षा-रोजगार-ट्रेनिंग से बाहर यानी NEET युवा और महिलाएं शामिल हैं.

NEET युवाओं के लिए सस्ती ट्रेनिंग की जरूरत

नीति आयोग ने 15 से 29 साल के उन युवाओं को NEET श्रेणी में रखा है, जो शिक्षा, रोजगार या ट्रेनिंग से जुड़े नहीं हैं. इसमें बेरोजगार युवा भी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, NEET युवाओं के सामने आय का अभाव और पहले की पढ़ाई पर किया गया खर्च बड़ी बाधा है. ऐसे युवाओं के लिए किफायती या सब्सिडी वाली ट्रेनिंग के साथ जरूरत के मुताबिक आर्थिक मदद भी जरूरी है. नीति आयोग ने कहा कि अलग-अलग वर्गों के लिए सीखने के साथ कमाई का रास्ता जोड़ना बेहद जरूरी है.

स्थानीय जरूरत और नए क्षेत्रों से जोड़नी होगी स्किलिंग

नीति आयोग ने कहा कि वर्कफोर्स और NEET युवाओं के लिए मिड-कैरियर रिस्किलिंग, स्वरोजगार के रास्ते और स्थानीय मांग के साथ उभरते क्षेत्रों से जुड़ी ट्रेनिंग पर ध्यान देने की जरूरत है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युवाओं को ऐसी स्किलिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वे सिर्फ नौकरी तलाशने वाले न बनें, बल्कि अपनी क्षमता के आधार पर स्वरोजगार भी शुरू कर सकें.

कम आय वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त खर्च बन रहा चुनौती

रिपोर्ट के मुताबिक, खासतौर पर कम आय वाले परिवारों से आने वाले छात्र पहले से ही कॉलेज की फीस और कई मामलों में निजी ट्यूशन के खर्च से दबे हुए हैं. ऐसे में पारंपरिक डिग्री के साथ अलग से महंगी स्किलिंग करना उनके लिए आर्थिक रूप से मुश्किल हो जाता है. नीति आयोग ने बताया कि इसी वजह से कई छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक मदद के लिए नौकरी या आय का कोई स्थिर जरिया तलाशते हैं. कई बार उन्हें कम वेतन वाली नौकरी भी स्वीकार करनी पड़ती है. वहीं, कुछ युवा पढ़ाई से नौकरी की तरफ सफलतापूर्वक नहीं बढ़ पाते और NEET श्रेणी में चले जाते हैं.

सीमा विवाद को लेकर चीन जाएंगे NSA अजीत डोभाल

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कूटनीतिक बातचीत एक बार फिर आगे बढ़ने जा रही है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार (24 अगस्त 2026) को बीजिंग पहुंचेंगे. वहां वह अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ भारत-चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स (SR) वार्ता में हिस्सा लेंगे. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अजीत डोभाल और वांग यी मंगलवार को सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत के 25वें दौर में शामिल होंगे. अजीत डोभाल और वांग यी दोनों भारत-चीन सीमा बातचीत के लिए नियुक्त स्पेशल प्रतिनिधि हैं. दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए यह विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाया गया था. इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान तलाशना है. दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को लेकर कई क्षेत्रों में मतभेद रहे हैं. भारत और चीन ने सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स तंत्र स्थापित किया था।

पड्डिकल के नाम रहा कोलंबो टेस्ट का पहला दिन

लगातार दूसरे टेस्ट में लगाया शतक, भारत का स्कोर 300/5

नई दिल्ली। देवदत्त पडिक्कल के शतक के दम पर भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में है। हालांकि, टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवा दिए हैं लेकिन पहले दिन ही 300 रनों के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत को दिन के अंत में बड़ा झटका लगा, जब रवींद्र जडेजा दिन के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने पहले दिन 300 रन बना लिए हैं लेकिन 5 विकेट भी गंवा दिए हैं। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 भारतीय बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। भारत के लिए ध्रुव जुरेल और सारांश जैन क्रीज पर मौजूद हैं, जो दूसरे दिन बैटिंग करेंगे।

भारत के लिए नंबर तीन की समस्या खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। देवदत्त पडिक्कल ने पहले मैच के बाद दूसरे मैच में भी शतक जड़ दिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2024 के बाद पहली बार वापसी की और लगातार दो शतक जड़े। इसी के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के बाद पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने नंबर तीन पर खेलते हुए लगातार दो मैचों में शतक लगाया है। पुजारा ने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में शतक लगाया था।

भारत की खराब शुरुआत

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी की, जबकि जायसवाल ने अटैकिंग क्रिकेट खेला। भारत को पहला झटका राहुल के रूप में लगा, जब श्रीलंकाई गेंदबाज लहिरू कुमारा ने उन्हें 18 रन पर आउट किया। जायसवाल आक्रामक खेल को जारी रखना चाहते थे लेकिन वे भी 45 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया ने 66 रनों पर ही दो विकेट गंवा दिए।

शुभमन गिल ने लगाया अर्धशतक

गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला था। हालांकि, दूसरे मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की और देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 120 रन जोड़े। गिल ने इस दौरान अर्धशतक लगाया लेकिन फिफ्टी जड़ने के बाद भारतीय कप्तान ने अपना विकेट गंवा दिया। गिल ने 108 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली।

ऋषभ पंत चोटिल; रिटायर्ड हर्ट हुए

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बैटिंग करते समय चोटिल हो गए. इसके बाद उन्हें रिटायर्ड होना पड़ा. पंत पहले दिन के तीसरे सेशन में पुल शॉट खेलते हुए चोटिल हुए. पहले दिन के तीसरे सेशन में श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा ने ऋषभ पंत को शॉर्ट गेंद डाली. इस गेंद पर ऋषभ पंत ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बजाय सीधे उनके बाएं हाथ पर जा लगी. चोट लगने के बाद पंत दर्द से कराहते दिखाई दिए. भारतीय टीम के फिजियोथेरेपिस्ट ने मैदान पर आकर उनका इलाज किया, लेकिन पंत का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था. ऋषभ पंत के हाथ पर पहले 'आइस पैक' लगाया गया और फिर पट्टी बांधी गई, लेकिन दर्द ज्यादा होने के कारण पट्टी भी जल्द हटा दी गई. पंत ने 15 गेंदों में तीन रन पर थे. हालांकि वह पारी के 58वें ओवर में फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मैदान से बाहर चले गए. इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए।

BCCI को नहीं मिल रहा टाइटल स्पॉन्सर

नई दिल्ली। अगर आप से कहा जाए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. पर यकीन मानिए ऐसा सच है. बीसीसीआई को टीम इंडिया के भारत में खेलने वाले मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिला है, क्योंकि ज्यादा कीमत की वजह से इन अधिकारों को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. इसके लिए बिड जमा करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त होने के बावजूद बीसीसीआई को या तो अधिकारों के लिए कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला या फिर बोलियां उम्मीद के मुताबिक नहीं थीं. बीसीसीआई ने 20 जुलाई को निमंत्रण जारी किया था और आईटीटी दस्तावेज खरीदने की आखिरी तारीख 4 अगस्त थी. बीसीसीआई ने स्पष्टीकरण मांगने की आखिरी तारीख 5 अगस्त रखी थी. बोर्ड संभावित स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें गूगल जेमिनी भी चर्चा में शामिल ब्रांड्स में से एक है. स्पिनी और एसबीआई लाइफ भी हैं. बीसीसीआई के मौजूदा अधिकार धारक - आईडीएफसी फर्स्ट बैंक - प्रत्येक मुकाबले के लिए 4.2 करोड़ रुपए का भुगतान करते हैं, लेकिन बेस प्राइस को बढ़ाकर 4.75 करोड़ रुपए करना संभावित डील के लिए एक बड़ी बाधा लग रहा है. यह डील दो साल के लिए थी, जबकि 2023 में आईडीएफसी बैंक को तीन साल के लिए अधिकार मिले थे. भारतीय बोर्ड ने अपने आईटीटी में पुष्टि की थी कि उसे उम्मीद है कि अधिकार धारक लगभग 35 मुकाबलों की मेजबानी करेगा.

बांग्लादेश में गैस न मिलने से रसोई से हाईवे तक हाहाकार

नई दिल्ली। बांग्लादेश इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर प्राकृतिक गैस और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. नैचुरल गैस की कमी के कारण कई उद्योग बंद हो गए, जिससे घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है. देश भर में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही है और ईंधन की कमी को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. मौजूदा समय में हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि देश में लगभग 3800-4000 मिलियन घन फीट की दैनिक मांग के मुकाबले केवल 2100-2400 mmcfd गैस ही मिल पा रही है. बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है. देश की 80% विदेशी कमाई का यही जरिया है. गैस का प्रेशर न होने के कारण सैकड़ों कपड़ा और कताई मिलों में उत्पादन आधा रह गया है. कई तो बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं. देश के 6 बड़े यूरिया उर्वरक संयंत्रों में से कई गैस न मिलने के कारण पूरी तरह से बंद हैं. इन्हीं में से एक है आशुगंज फर्टिलाइजर फैक्ट्री, जो मार्च 2025 में बंद हो गई थी. कभी यहां मशीनें चौबीसों घंटे चलती थीं और नैचुरल गैस का इस्तेमाल करके यूरिया बनाती थीं, जिस पर देश की 17 करोड़ आबादी के लिए फसलें उगाने वाले किसान निर्भर थे. कभी 1200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली यह सरकारी फैक्ट्री जंग खाकर बेकार पड़ी है. देश गैस की भारी कमी से जूझ रहा है.

नीदरलैंड से हारी टीम इंडिया, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर

नई दिल्ली। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान नीदरलैंड ने भारतीय टीम को हरा दिया है. नीदरलैंड ने 3-1 से भारत को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं इस हार के बाद भारतीय टीम अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है.

टीम इंडिया के लिए यह मैच करो या मरो वाला था, क्योंकि अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में यह मैच जीतना था. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम को अब दूसरे दौर का आखिरी मैच सोमवार को अर्जेंटीना से खेलना है. इसके बाद टीम पांचवें से आठवें स्थान के क्लासीफिकेशन मुकाबले खेलेगी.

भारत के लिए मैच में एकमात्र गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 52वें मिनट में किया. नीदरलैंड के लिये डुको टेलगेनकेम्प, येप होडेमेकर्स और वान डैम यिप ने गोल दागे. इस जीत के साथ डच टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही. पहले दौर में इंग्लैंड से हारने वाली भारतीय टीम दूसरे दौर में कोई अंक लेकर नहीं आई थी. अब अर्जेंटीना को हराने के बाद भी उसके तीन ही अंक होंगे, जिससे उसके अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई है।

सारांश जैन 21वीं सदी में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

कोलंबो। स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया. रविवार (23 अगस्त) से भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की शुरुआत हुई, जिसमें 33 साल के सारांश को मौका मिला. यह टेस्ट के साथ-साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू भी रहा. सारांश 21वीं सदी में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. इसके साथ उन्होंने 28 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. सारांश का 33 साल और 145 दिन की उम्र में डेब्यू हुआ. इससे पहले भारत के लिए 1998 में रॉबिन सिंह ने 35 साल और 23 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. इस तरह सारांश भारत के लिए 21वीं सदी में डेब्यू करने सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बने. वहीं बात करें टीम इंडिया के लिए सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू की, तो यह रिकॉर्ड रुस्तमजी जमशेदजी के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 41 साल और 27 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ ही एक टेस्ट खेला. उनका डेब्यू दिसंबर 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था।

इस हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद

नई दिल्ली। कल से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है. 24 से 30 अगस्त के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक शाखाएं कुल 4 दिन बंद रहेंगी. RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इस हफ्ते 24 से 30 अगस्त के बीच तीन रीजनल बैंक हॉलिडे हैं. आने वाले वीकेंड पर बैंक शनिवार को खुलेंगे क्योंकि 29 अगस्त महीने का पांचवां शनिवार है.

25 अगस्त, मंगलवार - केरल और आंध्र प्रदेश में बैंक मिलाद-उन-नबी या मिलाद-ए-शरीफ और ओणम के कारण बंद रहेंगे.

26 अगस्त, बुधवार - महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैंक ईद-ए-मिलाद, बारावफात या मिलाद-उन-नबी और तिरुओणम के उत्सव के कारण बंद रहेंगे.

28 अगस्त, शुक्रवार - रक्षाबंधन के चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

30 अगस्त, रविवार – वीकेंड की छुट्टी रहेगी।

डेबिट कार्ड का नियम बनेगा UPI की ढाल

नई दिल्ली। भारत में यूपीआई का क्रेज जबरदस्त है और उसका कारण है इसमें लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं (Zero MDR) देना पड़ता है. हालांकि, इसी के चलते Google Pay, Phonepe जैसी फिनटेक कंपनियों को भारी खर्च उठाना पड़ता है इसलिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की मांग लगातार उठती रही है.

सूत्रों के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का 2017 का एक नियम, जो दुकानदारों को डेबिट कार्ड की फीस ग्राहकों पर डालने से रोकता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूजर्स को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फीस से बचाने के लिए एक मॉडल बन सकता है. आरबीआई ने डेबिट कार्ड के लिए जो नियम बनाए हैं, अगर उन्हें यूपीआई पर थोड़े-बहुत बदलाव के साथ लागू किया जाए, तो यह आम जनता को नाराज किए बिना एक संतुलित शुल्क मॉडल का सटीक ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, 20 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले छोटे मर्चेंट्स के लिए डेबिट कार्ड पर MDR की ऊपरी सीमा बहुत कम (अधिकतम 0.40%) तय की गई है. आरबीआई का यह नियम 20 लाख से कम कमाई वाले मर्चेंट्स को MDR से बचाता है. यूपीआई पर इसके इस्तेमाल के तहत, छोटे किराना स्टोर्स या रेहड़ी-पटरी वालों को MDR शुल्क से 100% मुक्त रखा जा सकता है. वहीं डेबिट कार्ड के नियम अनुसार, बड़े-बड़े शोरूम, मॉल्स, ई-कॉमर्स कंपनियों से बैंक ज्यादा MDR वसूलता है. इस नियम को लागू करते हुए केवल बड़े संगठित रिटेलर्स और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर ही मामूली MDR लगाया जाए क्योंकि ये इस लागत को सहने के काबिल हैं.

आम जनता को मिलेगी राहत

इस नियम के लागू होने से आम उपभोक्ताओं के लिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे भेजना हमेशा की तरह 100% फ्री रहेगा. NPCI और फिनटेक कंपनियों के लिए भी रेवेन्यू जेनरेट होगा, जिसका इस्तेमाल वे अपने सर्वर और सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कर सकेंगे. वर्तमान में सरकार को कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए करोड़ों रुपये का इंसेन्टिव फंड देना पड़ता है.

31 अगस्त तक कर भरना होगा रिटर्न; वर्ना जुर्माने के लिए रहें तैयार

YouTube से कमाई नहीं है टैक्स फ्री

कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं होती है. एक यूट्यूबर AdSense से पैसे कमा सकता है, Instagram क्रिएटर के लिए ब्रांड डील पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया है. इसके अलावा, एफिलिएट कमीशन, मेंबरशिप, सुपर चैट, प्लेटफॉर्म से मिलने वाले पेमेंट और यहां तक कि मर्चेंडाइज बेचकर भी कमाई हो सकती है. डिजिटल इकोनॉमी से होने वाली इस कमाई पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर रहती है.

ऐसे में अगर आप भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और Instagram, YouTube या Facebook से मोटी कमाई कर रहे हैं, जो आपके लिए भी 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन अहम है. कारोबारी साल 2025-26 के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है और जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी नहीं है. यदि इस तारीख तक क्रिएटर्स ने अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो उन्हें भारी जुर्माना और कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.

इन 5 तरह की कमाई पर लगता है टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की इन सभी स्त्रोतों से होने वाली आय 'Profits and Gains from Business or Profession' (PGBP) या 'Income from Other Sources' के तहत टैक्स के दायर में आती है:

एड रेवेन्यू- यूट्यूब मोनेटाइजेशन और वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों से होने वाली सीधी कमाई.

स्पॉन्सर्ड पोस्ट- किसी ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के बदले मिलने वाला पैसा.

मर्चेंडाइज और पेड सब्सक्रिप्शन- अपने नाम के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बेचने या यूट्यूब 'जॉइन' बटन/फैन सपोर्ट से होने वाली आय.

एफिलिएट मार्केटिंग- बायो या डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक के जरिए सामानों के बिक्री के बदले मिलने वाला कमीशन.

फ्री प्रोडक्ट्स और गिफ्ट्स- टैक्स नियमों के अनुसार, अगर कोई कंपनी या ब्रांड आपको प्रमोशन के लिए मोबाइल, कार, लैपटॉप जैसी चीजें मुफ्त में देता है या फ्री में विदेश की सैर कराता है, तो उस पर 10% की दर से TDS कटता है.

31 अगस्त की डेडलाइन चूकने से नुकसान

31 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करने पर पहले तो आपको 1000-5000 रुपये तक लेट फीस देनी होगी. साथ ही टैक्स देनदारी पर प्रति माह 1% की दर से अतिरिक्त ब्याज चुकाना हागा. टैक्स चोरी करने या विदेशी आय (यूट्यूब से डॉलर में होने वाली कमाई) को छुपाने पर आयकर विभाग का सख्त नोटिस भी आ सकता है.

रिकॉर्ड तोड़ सकता है सोना, मौजूदा स्तर से दोगुनी हो सकती है चांदी की कीमत

नई दिल्ली। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता, शेयर बाजारों के उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में दोनों कीमती धातुओं में बड़ी रैली आ सकती है. विशेषज्ञों ने आम उपभोक्ताओं और निवेशकों को सलाह दी है कि वे कीमतों में किसी बहुत बड़ी गिरावट का इंतजार न करें, बल्कि बाजार में आने वाले हर छोटे-बड़े सुधार को खरीदारी के एक अच्छे मौके के रूप में इस्तेमाल करें.

कमोडिटी विशेषज्ञ और मार्केट रिसर्चर डॉ. अनुज गुप्ता के अनुसार, हाल के दिनों में सोने की कीमतों में 5.13 प्रतिशत का भारी उछाल आया है, जिससे घरेलू बाजार में यह 1,62,438 रुपये प्रति 10 ग्राम के 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना 5.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,602 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. दूसरी ओर, चांदी की कीमतों में भी 4.52 प्रतिशत की जोरदार तेजी दर्ज की गई और यह 2,46,597 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई. जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में भी यह ट्रेंड बुलिश रहेगा।

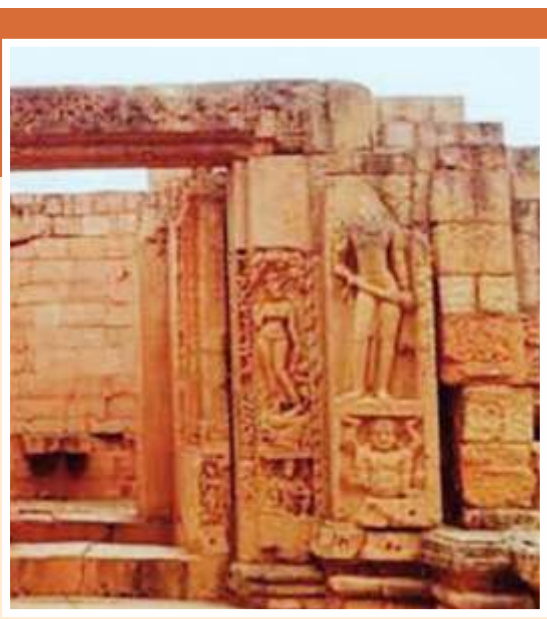

छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन दुर्ग विन्यास का विस्तार और स्वरूप

डा. टी. आर. रामटेके

छत्तीसगढ़ में दुर्गीकृति नगरों के निवेश या नगराकर दुर्गों के विन्यास की परंपरा के अतिरिक्त कालांतर में एक और पद्धति पनपी। वह यह कि नगर के अभ्यंतर प्रदेश में या किसी कोण पर अथवा नगर से कुछ दूरी पर दुर्गों का सन्निवेश होने लगा। मध्यकालीन राजधानियां व प्रमुख नगर इसके उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से लेकर कलचुरी काल तक लगभग सौ किले निर्मित हुए। जबकि छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल के छत्तीस किलों को छोड़कर लगभग अस्सी किलों के पुरावशेष विद्यमान हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग निवेश का जो विवरण प्राप्त होता है, उसके अनुरूप मल्हार में आटविक मही दुर्ग के प्राकार, परिखा, वप्र व प्रासाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। मौर्य युग का गढ़ मल्हार बिलासपुर जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में 32 कि मी दूरी पर स्थित है। बिलासपुर रायगढ़ मार्ग पर बिलासपुर से 18 कि मी दूरी पर मस्तूरी है जहां से 14 कि मी मस्तूरी चिल्हाटी मार्ग पर मल्हार स्थित है। मल्हार से प्राप्त कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव द्वितीय के शिलालेख में मल्हार का प्राचीन नाम मल्लाल दिया गया है। वहीं से प्राप्त एक शिलालेख में इसे मल्लाल पत्तन कहा गया है। प्राचीन काल में इस नगर का विस्तार दस वर्ग मील के क्षेत्र में विद्यमान था। मल्लाल पत्तन नगर तीन नदियों से घिरा था। इसके पश्चिम में अरपा नदी, पूर्व में लीलागर नदी और दक्षिण में शिवनाथ नदी है।

बड़ महत्व के होथे सवनाही बरोई

रोशन लाल

कोनो भी परब तिहार मनाये पाछू कतकोन कारन होथे। आधुनिक मनखे मन ल कतकोन रीत-नीत भले दकियानूसी लग सकत हे। फेर ओखर जर मूल ल बनेच विचार करबे त माने ल परथे कि सबो रीत-नीत ह कुरीति कुप्रथा नोहे, येमा वैज्ञानिकता घला सिद्ध होथे। असाढ़ पाछू सावन आथे गांव-गंवई म सवनाही बरोय जाथे। ये खातिर गांव के बइगा अउ एक दू सुजानिक मनखे अधरतिहा म गांव के सबो देवी-देवता जइसे शीतला देवी, सत बहिनिया, फिरन्तीन देवी, परेतिन दाई, घुमियार देवता, ठाकुर देवता, घनश्याम देवता, सांहड़ा देवता, बइगा देवता, हाखड़ी देवता, बघरेन देवता, अखरा देवता, मसान देवता, भंगाराय, राव देवता, भैंसा सुर, बाई देवता, नादिया देवता, बूढ़ा देव, सेमरा देवता, बारा देव, खेतपाल देवता, बांधा देव, कोतवाल देवता, डहरिया देव, नाग देव, गोड़ा देवता, भूमिया देवता अउ आने-आने देवी-देवता माने जथे।

गांव के सबो देवी-देवता के मान-गउन के जिम्मेदारी बइगा के होथे। जेखर खातिर गांव वाले मन उनला 'जेवर' समर्पित करथें। मान-गउन म भूल-चूक होथे त जानकारी होई जथे। कभू जोत-जंवारा बोहईया बहू-बेटी मन के रोवई-ललई ले, त कभू गांव के सियान ल सपना म आके बताथें, त कभू बइगा के तन म तिरशूल साँकर के चीन्हा, त कभू लोर उपक जाये रहिथे। गांव म कोन्हों भी उछाह परब होय चाहे कोनो भी सुख दुख के काम काज। समे-समे म देवी-देवता के मान गउन करे जाथे। सवनाही बरोय खातिर गांव के बइगा अउ एक दू सुजानिक मनखे अधरतिहा म गांव के सबो देवी-देवता ल सुमर के हूम-धूप नरियर-फ़राटा ले मना पथा के गांव के मेड़ो जेन ल गांव के सियार घलो कहिथन, तिंहा जाथें। जिहाँ सवनाही बरोय के पाछू कभू लहुट के देखे नई जाये। रेंगाय सवनाही ल जेन मनखे देख परे हे तेन देवारी नई देख पाये हवे। अइसनो बात देखे सुने म आये हवे। फेर बरोय के बात ल लोगन मन ल नई बताय जाय। काबर कि कोन्हों खपचलहा टोना-टोटका करइया मनखे सवनाही ल झन लहुटाये। माने जाथे कि येकर लहुटे ले गांव बस्ती म नाना किसम के अल्हन आथे। गाय-गरुवा म बीमारी, लोग-लइका के तबियत खराब होवई, रूख-राई धान-पान म कीरा-काँटा झपा जथे। सवनाही बरोय बर नीम लकड़ी के तिकोन रथ, लाल करिया अउ सफेद रंग के ध्वजा, करिया पिंयर चाँउर, नीमउ, बन्दन पिंवरी सरसों, उल्टा पाँख के करिया कूकरी या चिंया, अंडा, दीया-बाँती, हूम-धूप अगरबत्ती कतकोन जिनिस लगथे। कहे जाथे-

'हरेली ले बाँचे,
ते देवारी में नाचे'

जुन्ना समे म घुप्प अंधियारी सावन-भादो, न तो बिजली न बत्ती। उपराहा म पंदराही बिसोंधी ले सरलंग झमाझम झड़ी बादर, सबो डाहर चिखला माते राहय। त अईसन म संक्रामक रोग-राई अउ हैजा प्लेग असन जीवलेवा महामारी फैल जाये।

जुन्ना समे म प्रकृति ले सोझे जुड़ाव कारन प्राकृतिक, घरेलू आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति धनिया, जीरा, सोनामखी, नीम, हर्रा, बहेरा अउ तिर-तखार जड़ी-बूटी पाना-पतुव्वा ले ईलाज होवय। तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका, झाड़-फूंक घलो। सार बात ये आय कि गांव के सबो बिधन-बाधा, गांव के बीमारी ल टारे बर सवनाही बरोय जाथे। एक बात जरूर हवे कि सवनाही बरोवत बेरा बइगा के वचन के गज्जब महत्तम हे। जब बइगा कथे- 'रजा रे सवनाही जेन ह तोला पहिली देखही तेला खा लेबे।' त फेर कोनो सरल सुभाव वाला बइगा कहिथे- 'रजा रे तैंय हमर गांव के सबो बिधन-बाधा कारू-नारू ल टार दे।' त कोन्हों ल नुकसान नई करे। अईसे माने गेय हवे। सवनाही बरोय के आधू दिन गांव म तिहार मनाये जथे। लोगन खेत-खार जवई-अवई नई करय न काम-काज। येखर पाछू इहि मान्यता हवे कि रतिहा म बरोय हुए ल कोनो मनखे झन देखन पाय।

बरसात में मनमोहक होथे दंतेवाड़ा के मलगोर जलप्रपात

डा. डी. पी. देशमुख

बस्तर के दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल ले करीबन 8-10 कि.मी. दुरिहा पहाड़ी के बीच म कुवाकोंडा ब्लाक के गांव निलवाया के तीर म स्थित हे मलगोर जलप्रपात हा। ये जलप्रपात ह मलगोर पहाड़ी नदिया ले 60-70 फीट के ऊंचाई ले खाल्हे म गिरथे, एकर कल-कल छलछावत पानी के तेज धार ह खाल्हे गिरत बेरा म घोर गरजना ह हिरदे के धड़कन ल बढ़ा देथे, फेर एकर सुर-ताल ले रोमांचक संगीत ह मन ल मोह लेथे। घुमघुम ले जंगल-झाड़ी, ऊंच-ऊंच पहाड़, अऊ प्रकृति के अतीक सुघ्घर जलप्रपात ह आय-जाय के रद्दा नई होय ले जनमानस के नजर ले येहा अब्बड़ दूर हो गए हे। असुविधा होय के बाद घलो जानकार पर्यटक मन ये जगा के सुंदरता ल देखे बर कईसनो कर के पहुंच जाथे। प्रकृति के नजारा ह पर्यटक मन ल ये मेर आय म मजबूर कर देथे। कठिन सफर ले आय पर्यटक के मन ल सुकून ले भर देथे। येकर ले सरी थकान मेटा जाथे। कहू आय जाए के रास्ता सुगम हो जहि तब पर्यटक मन बर पिकनिक के एक अउ ए सुघ्घर जगा हो सकत हे।

छत्तीसगढ़ी में हाइकू लेखन

श्यामा सिंह

छत्तीसगढ़ी साहित्य लेखन की समृद्ध परंपरा हमें दिखाई देती है। कई विधाओं के लेखन ने समाज की विसंगतियों को आगे लाकर जन जागरण का भी कार्य किया है वहीं कुछ विधाओं में लेखन की कमी भी महसूस की जा रही है। इसी कड़ी में हाय्कू लेखन पर नजर डालें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तथा उसके कई सालों बाद तक इस लेखन के प्रमाण सामने नहीं आए। छत्तीसगढ़ी का प्रथम हाय्कू प्रदीप कुमार दास 'दीपक' रचित 'मइनखे के पीरा' (2000 ई.), हाय्कू चतुष्क (चार भाषाओं में 2001 ई) और छत्तीसगढ़ की हाय्कू साधना जैसे -

बापू के फोटू
आफिस मा बहाथे
ओकर आंसू (मनखे के पीरा)

प्रदीप शर्मा रचित चंद हाय्कू, बिट्ठल राम साहू निश्छल रचित जिनगी होगे चिरहा दौना संगी, अन्य छत्तीसगढ़ी हाय्कू रचनाकारों में डा राम नारायण पटेल, डिहुरराम निर्वाण प्रतप्त, राम साहू अकेला, प्रो. आदित्य प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, देवेंद्र नारायण दास, उमा देवी दीक्षित, पुरुषोत्तम छत्तीसगढ़िया, पंखनाम गौतम के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके बाद अभी और नाम नहीं आ रहे हैं। स्पष्ट है कि इस विधा में भी लेखकों को छत्तीसगढ़ी साहित्य की इस विधा में अपनी कलम चलाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय जागरण का गीत ददरिया

छत्तीसगढ़ी श्रृंगारिक लोकगीतों में ददरिया का प्रमुख स्थान है। यह गीत नारी पुरुष अकेले और संयुक्त रूप से गा सकते हैं। कभी कभी यह गीत संवादात्मक भी होते हैं। इन गीतों के गाने के लिए किसी प्रसंग विशेष की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। प्रातःकाल का मनोहारी दृश्य कोमल नारी स्वर में हृदय को छू लेता है। राष्ट्रीयता और समर्पण का भाव भी ददरिया गीतों का विषय बना है -

सब दुख के दवाई सुनो एक हे सुराज,
सबला भुला के विचार देखो आज।

यहां तक की भावत्मक एकता का प्रयास भी ददरिया में देखने को मिलता है -

हिन्दू अउ पठान एके मा मिलके,
हम लेबोन गा सुराज सबो झिन भिड़के।

छुइहा सरोवर के तीन छोर पर शिवालय में सावन माह भर लगता है भक्तों का मेला

जिला बलौदा बाजार - भाटापारा अंतर्गत ग्राम हसुआ में 1890 में विशाल छुइहा सरोवर के तीन छोर पर खरौद नगर के कारीगरों द्वारा विशाल शिवालय स्थापित किया गया। तालाब व मंदिर निर्माण में यहां के मालगुजारों का विशेष योगदान रहा। पूजा अर्चना विधिवत पुजारियों द्वारा तो किया ही जाता है। साथ ही भक्त महाशिवरात्रि और पूरे सावन माह भक्तों की अपार भीड़ देखी जाती है। इस माह कावड़ियों को जल अर्पित करते भी देखा जाता है। धार्मिक व मांगलिक कार्यों में भी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने भक्त मंदिर पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह प्राचीन शिवालय क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सावन के दिनों में मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है। दूर-दराज के गांवों से भी लोग यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सरोवर के शांत वातावरण और मंदिर की प्राचीन स्थापत्य शैली श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष पूजा, अभिषेक और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं।

डीज़ल-पेट्रोल घोटाला करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाए एडीजी गुप्तवार्ता ने बदली व्यवस्था

वाह साहब; रोक नहीं सके तो मुंह मोड़ लिए

एसबी-एमटी पुल में व्याप्त अनियमित्ता के चलते वीआईपी बटालियन कमांडेंट जिम्मा

- एडीजी इंट अमित कुमार ने पेट्रोल-डीज़ल की गडबडी को रोकने के लिए उठाये पुख्ता कदम
- अब एसबी-एमटी पुल में नहीं वीआईपी बीएन माना को पेट्रोल-डीजल डालने का आदेश जारी
- अब तक एसबी-एमटी पुल कर रहा था वीआईपी कोटा वाहनों की फ्यूलिंग और मेंटेनेंस
- एडीजी इंट अमित कुमार केआदेश के बाद अब एसबी-एमटी पुल के पास सिर्फ PHQ कोटा

पुलिस कोटा की गाड़ियों में हजारों लीटर डीजल-पेट्रोल कोटा में गड़बड़ियों की खबरें विधानसभा में भी गूंजने लगी है। वर्षों से वीआईपी और पीएचक्यू कोटा की सैकड़ों गाड़ियों में गंभीर अनियमित्ताओं की शिकायतें गुप्तवार्ता के आला अधिकारीयों तक पहुंच रही थी। जब तक मामला गर्म रहा तो खानापूर्ति के लिए जांच बैठाये जाने का भी दिखावा हुआ। लेकिन आज तक एसबी-एमटी पुल के किसी घोटालेबाज की मुश्कें नहीं कसी गईं। आखिरकार एडीजी गुप्तवार्ता अमित कुमार ने फ्यूल गड़बड़ी को रोकने के लिए एसबी-एमटी पुल से सभी वीआईपी कोटा वाहनों के लिए फ्यूलिंग का नया आदेश जारी किया हैं। अब से सभी वीआईपी कोटा की गाड़ियों, काफिलों के लिए पेट्रोल-डीजल की जिम्मेदारी वीआईपी बटालियन माना को सौंप दी है। माना जा रहा है कि घोटाला करने वालों के मुश्कें जब विभाग कस नहीं पाया तो व्यवस्था बदलकर मुंह मोड़ लिया।

शहर सत्ता/रायपुर। अब से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी वीआईपी कोटा की गाड़ियों की रिफ्यूलिंग माना स्थित वीआईपी बटालियन के कमांडेंट की देखरेख में होगी। एडीजी गुप्तवार्ता अमित कुमार ने यह आदेश 19 अगस्त 2026 को जारी किया है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी कोटा के अलावा पीएचक्यू कोटा की तकरीबन 400 गाड़ियों में अभी तक गुप्तवार्ता के अधीनस्थ एसबी-एमटी पुल से ही आरआई और एमटीओ पेट्रोल-डीजल का प्रभार देखते थे।

बताते हैं कि पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल का कोटा भी निर्धारित है। वीआईपी कोटा की गाड़ियों के लिए 600 लीटर माह और पीएचक्यू कोटा वाहनों के लिए 250 लीटर निर्धारित हैं। लेकिन एसबी एमटी पुल में हर महीने हजारों लीटर के डीजल घोटाले की खबरें अख़बारों की सुर्खिया बनने के बाद मामला विधानसभा में भी गूंजा था। लेकिन बावजूद इसके अब तक कथित घोटाले के एक भी सूत्रधार का पता छत्तीसगढ़ पुलिस के गुप्तवार्ता अधिकारीयों को नहीं चल पाया है। पूर्व मे हज़ारों लिटर डीज़ल घोटाला हुआ उसकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई लेकिन भविष्य मे वीआईपी कोटा की गाड़ियों में होने वाली गडबडी को रोकने के लिए विभाग ने वीआईपी कोटा वाहनों को वीआईपी बटालियन को सौंप दिया है।

तय कोटे से ज्यादा डीजल पी रहीं गाड़ियां

वीआईपी कोटा की गाड़ियों का लोकल रनिंग कोटा भी 600 लीटर महीना होता है, जबकि 250 लिटर का कोटा पीएचक्यू कोटा निर्धारित है। लेकिन राजधानी रायपुर समेत अन्य पुलिस जिलों में डीजल-पेट्रोल कोटा की जांच नहीं की गई है। नहीं चलने वाली गाड़ियों में भी सैकड़ों लीटर डीजल पी गई। सरकारी गाड़ियों के कोटे का डीजल-पेट्रोल अफसरों की प्राइवेट गाड़ियों में भी डालने का आरोप एसबी-एमटी पुल के आरआई-एमटीओ पर आरक्षक चालकों ने लगाया था।

एडीजी गुप्तवार्ता द्वारा जारी आदेश

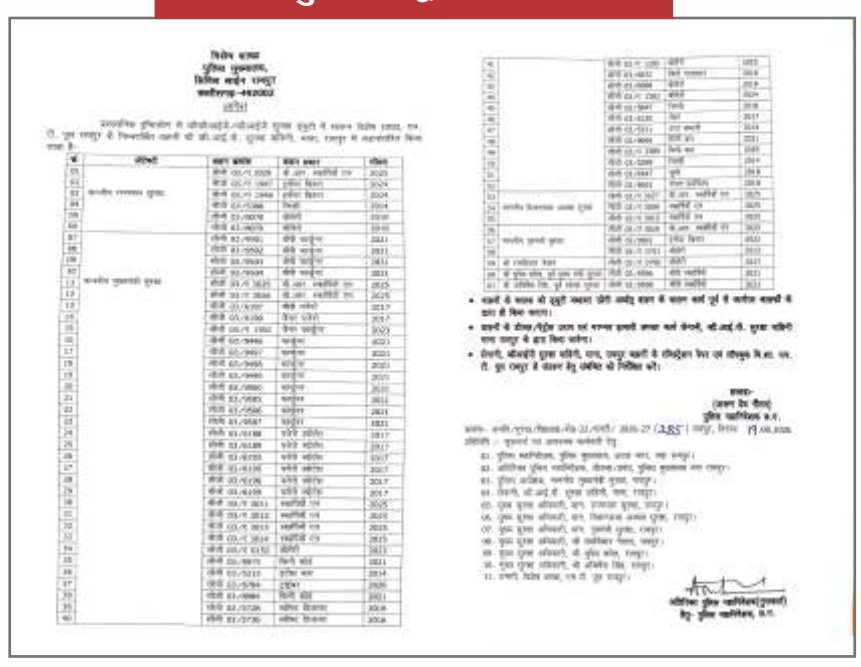

शिकायत के बाद भी खामोश गुप्तवार्ता

दोषियों पर कार्रवाई करने के बदले गुप्तवार्ता के अधिकारी आरक्षक चालकों पर ही करते दिखे। पूर्व में भी शहर सत्ता अखबार ने डीजल-पेट्रोल में गंभीर अनियमत्ता की खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसमें 110 लिटर डीज़ल चालक विनोद उइके गाड़ी नंबर cg 03 5314 सफारी का फ्यूल डीएसपी मणिशंकर चंद्रा की गाड़ी में डालने का आरोप लगाया था। सीजी-03-5921 सूमो का डीज़ल मणिशंकर की गाड़ी मे 28 जुलाई को स्कार्पियो में डाला गया था। इसकी जांच शिकायत के बाद भी नहीं हुई।

3 अगस्त को प्रकाशित खबर

एडीजी साब, सच जानना है तो दरबार लगाइए...

मनमानी ड्यूटी, डीज़ल-पेट्रोल पर्ची में गोलमाल के लिए आरक्षक चालकों पर दबाव

क्या व्यवस्था बदलने से रुकेगा घोटाला ?

आमतौर पर वीआईपी गाड़ियों में ही पेट्रोल डीज़ल घोटाला करना आसान है। इसकी फ्यूल और रनिंग कोटा का प्रति माह 600 लीटर निर्धारण है। लेकिन लॉग बुक, आरक्षक चालक को जारी पर्ची और पेट्रोल पंप से की गई फ्यूल रिसिप्ट से गड़बड़ियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। अगर विभागीय अधिकारी इसे लेकर गंभीर होते तो संभवतया छत्तीसगढ़ शासन और विभाग का पैसा बचाया जा सकता था। अब एसबी-एमटी पुल से यह जिम्मा वीआईपी बटालियन के कमांडेंट को दे दिया गया है। देखना यह है कि क्या व्यवस्था बदलने से चोरी-गड़बड़ी रुक जाएगी?

अभी भी एसबी-एमटी के पास PHQ कोटा

वीआईपी कोटे की गाड़ियों से मलाई खाने वाले एसबीएमटी पुल को अब महज 100 PHQ कोटा वाहनों से तसल्ली करना पड़ेगा। व्यवस्था बदलने के बाद भी PHQ कोटा गाड़ियों का प्रति माह 250 लीटर का डीजल निर्धारित है। ऐसे में अंदाज़ लगाया जा सकता है कि अब भी आरोपी अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि एसबी-एमटी पुल में संदिग्ध अफसरों के हाथ में ही कमान है। PHQ कोटा की गाड़ियों का डीजल, मेंटेनेंस इनके पास ही बरक़रार है।

नहीं होगा सर्वाइकल कैंसर, 14 साल तक की बालिकाओं को मिलेगा फायदा

छत्तीसगढ में अब किशोरियों को लगेगी HPV वैक्सीन

रायपुर। प्रदेश के पीएचसी में भी अब 14 साल तक की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार यह वैक्सीन कैंसर से बचाव के लिए 95 फीसदी कारगर है। पीरियड के समय हाइजीन मेंटेन नहीं करने व कम उम्र में शादी को सर्वाइकल कैंसर की मुख्य वजह माना जाता है।

टीकाकरण से पहले पालकों से सहमति

एचपीवी वैक्सीन की सिंगल डोज (0.5 मिली) लगाई जा रही है। यह अभियान उन अस्पतालों में चलाया जा रहा है, जहां मेडिकल अफसर पदस्थ हैं। वैक्सीन बायीं ऊपरी बांह में लगाई जाएगी। यह टीका गर्भावस्था अथवा खाली पेट में नहीं लगाया जाता। हालांकि प्रदेश में 15 वर्ष की किशोरियों की शादी नहीं होती। टीकाकरण के पश्चात तर्जनी उंगली में मार्किंग की जा रही है। टीकाकरण से पहले पालकों से सहमति ली जा रही है।

सर्वाइकल कैंसर के बचाव में 95 फीसदी कारगर

सीनियर कैंसर सर्जन डॉ. आशुतोष गुप्ता व हिमेटोलॉजिस्ट डॉ. विकास गोयल के अनुसार एचपीवी वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर के बचाव में 95 फीसदी कारगर है। किशोरियों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि भविष्य में गर्भाशय के मुख का कैंसर न हो। दरअसल ग्रामीण आबादी में कैंसर के सबसे ज्यादा केस गर्भाशय के मुख का कैंसर के हैं। जागरूकता के अभाव में व पीरियड के समय हाइजीन

मेंटेन नहीं करने तथा कम उम्र में शादी सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। केंद्र सरकार की फ्री वैक्सीनेशन योजना से किशोरियों को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकेगा।

पीएचसी में ही मिलेगी वैक्सीन की सुविधा

अब तक कई परिवारों को HPV वैक्सीन के लिए बड़े अस्पतालों या निजी केंद्रों का रुख करना पड़ता था। लेकिन अभियान के विस्तार के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों के लिए भी टीकाकरण की सुविधा आसान हो रही है। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हैं, वहां अभियान के तहत वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीकाकरण के दौरान 0.5 मिली की सिंगल डोज दी जा रही है। वैक्सीन बायीं ऊपरी बांह में लगाई जाएगी। टीका लगाने से पहले बालिका के माता-पिता या अभिभावक की सहमति ली जा रही है। टीकाकरण के बाद पहचान और रिकॉर्ड के लिए तर्जनी उंगली में मार्किंग भी की जा रही है।

क्यों जरूरी है HPV वैक्सीनेशन?

HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है, जिसके कुछ प्रकार आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर एक महत्वपूर्ण बीमारी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी के कारण समय पर जांच और बचाव के उपाय नहीं हो पाते। कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक HPV संक्रमण से बचाव के लिए किशोरावस्था में वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है। टीका संक्रमण होने से पहले दिया जाए तो इसका फायदा अधिक मिलता है। इसलिए बालिकाओं को कम उम्र में ही वैक्सीनेट करने पर जोर दिया जा रहा है।

ऐसे मिलेगा फायदा

- 14 साल तक की बालिकाएं अभियान के दायरे में हैं।
- HPV वैक्सीन की सिंगल डोज (0.5 मिली) दी जा रही है।
- टीका बायीं ऊपरी बांह में लगाया जाएगा।
- टीकाकरण से पहले पालक/अभिभावक की सहमति ली जाएगी।
- मेडिकल ऑफिसर वाले चयनित PHC में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है।
- टीकाकरण के बाद तर्जनी उंगली में मार्किंग की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27